सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 169, नई दिल्ली । गुरुवार, 29 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा हथियार है, अपने पौरुष को जगाओ और इस आजादी का जश्न मनाओ

03 लीला अवलोकन का न्यौता परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को

06 ओलंपिक पदक तालिका में सैन्य किरदार

08 प्रथम पूज्य गणपति प्रतिमाओं का वितरण होगा 7 सितंबर को

क्या जनता द्वारा व्यवसायिक वाहनों के लिए की गई शिकायते परिवहन विभाग में दर्ज भी होती हैं?

संजय बाटला

क्या कश्मीरी गेट बस अड्डे के अंदर से मध्य प्रदेश के लिए चल रही प्राईवेट बसों के मान्य दस्तावेज पूरे है भी या नहीं ?
क्या दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी द्वारा बनाए गए प्रवर्तन अधिकारी (ई ओ) उस पद पर आसीन होने की शर्तो/नियमों को पूरा करते हैं ?
विज्ञापनों द्वारा अपने आप की और दिल्ली सरकार को श्रेष्ठ दिखाने के लिए शुरू की गई प्रीमियम बस सेवा कहीं चल भी रही है या उसका लोगो बनकर विभाग और दिल्ली सरकार की अलमारी/ टेबल की दराज में ही अब तक पड़ा है?
क्या मोहल्ला बस सेवा के नाम पर चलाई जाने वाली बस किसी भी मोहल्ले में जाने लायक है ?
क्या भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिल्ली के सभी व्यवसायिक श्रेणी के पंजीकृत वाहनों में जीपीएस/ जीपीआरएस/ वीएलटीडी संयंत्र लगे हुए भी हैं या नहीं ?
क्या दिल्ली की आप पार्टी सरकार और

परिवहन विभाग के आला अधिकारी द्वारा दिल्ली की जनता की सुविधा और सहायता के लिए नोटिफाई करके खोले गए क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने के पीछे क्या उद्देश्य है ?
क्या आप जानते हैं आला अधिकारी परिवहन विभाग के द्वारा तकनीकी पदों पर जानबूझ कर गैर तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति और गैर तकनीकी पदों पर तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति के पीछे क्या उद्देश्य है ?
क्या आप जानते हैं एमएलओ का नाम बदल कर डीटीओ करवाने के पीछे परिवहन विभाग के आला अधिकारी का क्या उद्देश्य है?
क्या आप जानते हैं दिल्ली परिवहन विभाग को पिछले 11 वर्षों में एक भी बस ना खरीद कर देने के पीछे क्या उद्देश्य है?

अभी अनगिनत बाते और सवाल बाकी है जिनके जवाब दिल्ली की जनता के लिए जानना अति आवश्यक है पर अभी दिल्ली के उपराज्यपाल जनता के समक्ष पूछे गई बातों को ही सपष्ट कर दे तो जनता को परिवहन विभाग के आला अधिकारी का सच दिख जाएगा।

क्या आप जानते हैं

संजय बाटला

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 भारत में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इसे 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया था और इसके तहत कई नए प्रावधान और सख्त नियम पेश किए गए हैं। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. सुरक्षा और दंड

दंड की वृद्धि: कई ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए दंड की राशि में वृद्धि की गई है, जैसे कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना, और ओवरस्पीडिंग।

चालान: उल्लंघनों के लिए चालान की प्रक्रिया को डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और ट्रैफिक पुलिस के लिए निगरानी आसान हुई है।

2. ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन

लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का नवीकरण: अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन का नवीकरण डिजिटल माध्यम से भी किया जा सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस की नई श्रेणियाँ: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नई श्रेणियाँ और मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिससे लाइसेंस की प्रक्रिया और मान्यता को मजबूत किया गया है।

3. सड़क सुरक्षा

सड़क दुर्घटनाओं में राहत: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता देने के लिए व्यवस्था की गई है।

वाहन और ड्राइवर सुरक्षा: वाहनों के डिजाइन और ड्राइवर के प्रशिक्षण पर नए मानक लागू किए गए हैं, जैसे कि वाहन में एयरबैग और ABS ब्रेक सिस्टम।

4. समानता और जवाबदेही

सार्वजनिक परिवहन: सार्वजनिक परिवहन के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिनमें नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिक सख्त प्रावधान शामिल हैं।

वाहन पर सेन्सर: वाहनों में सेन्सर और अन्य सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्यता बढ़ाई गई है।

5. ट्रैफिक प्रबंधन

ऑनलाइन सेवाएँ: ट्रैफिक संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने के लिए प्रणाली को बेहतर किया गया है, जिससे लोगों को सुविधा मिलती है और प्रक्रियाएं तेजी से पूरी होती हैं।

डिजिटल चालान: डिजिटल चालान प्रणाली लागू की गई है, जिससे चालान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल बन गई है।

6. स्वतंत्रता और प्रशासनिक सुधार

संविधानिक अधिकार: मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में राज्य सरकारों को भी अधिक स्वतंत्रता दी गई है, जिससे वे अपने स्थानीय ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर तरीके से लागू कर सकें।

अधिक प्रभावी निगरानी: ट्रैफिक उल्लंघनों और नियमों के पालन पर अधिक प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी उपकरण और तकनीक की व्यवस्था की गई है।

इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इसके तहत नए नियम और सख्त दंड सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए हैं और यह सड़क पर बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और नियमों के पालन को बढ़ावा देता है।

दिल्ली परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 7 दिनों में स्क्रैप किए जाएंगे अवैध ई-रिक्शा; फैसले के पीछे है बड़ी वजह

दिल्ली परिवहन विभाग ने अवैध ई-रिक्शा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अब पकड़े जाने के बाद अवैध ई-रिक्शा को सात दिनों के भीतर स्क्रैप कर दिया जाएगा। यह फैसला स्क्रैप डीलरों के माध्यम से इन ई-रिक्शा के दोबारा सड़कों पर आने की आशंका को देखते हुए लिया गया है। परिवहन विभाग का कहना है कि सबसे ज्यादा शिकायतें ई-रिक्शा के खिलाफ ही मिलती हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। परिवहन विभाग ने पकडे. जाने के बाद अवैध ई-रिक्शा को स्क्रैप करने के मामले में नियमों में बदलाव कर दिया है। अब कंडम करने के बाद ही स्क्रैप के लिए ई-रिक्शे दिए जाएंगे। परिवहन विभाग स्वयं इन्हें अपने केंद्र में तुड़वाएगा। इसके बाद ये स्क्रैप डीलर को दिए जाएंगे। स्क्रैप डीलर के यहां से फिर से अवैध ई-रिक्शा सड़कों पर आ जाने की आशंका से यह फैसला लिया गया है। बुधवार को पहली बार पकडे.गए ई-रिक्शा को जेसीबी से तोड़ा गया।

परिवहन का इस समय पूरा फोकस अवैध ई-रिक्शा पर है। इनकी वृद्धि को रोकने के लिए ही दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने जब्त किए गए गैर पंजीकृत ई-रिक्शा को सात दिनों के भीतर खत्म करने का फैसला किया है।जबकि नियमों के तहत पंजीकृत ई-रिक्शा को स्क्रैप करने से पहले केंद्र पर रखने की अवधि 90 दिन है।

भीड़भाड़ कम करने के लिए हुई उच्च स्तरीय समीक्षा

उपराज्यपाल की अध्यक्षता में गत दिनों शहर में भीड़भाड़ कम करने के उपाय को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी। उसके बाद से अवैध रूप से चलने वाले ई-रिक्शा कर कार्रवाई का निर्णय लिया गया था। इस पर अमल करते हुए परिवहन विभाग ने अवैध रूप से चलने वाले ई-रिक्शा कर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी माह अभी तक विभाग की टीमों ने 1600 से अधिक अवैध ई-रिक्शे पकड़े हैं।

प्रतिदिन 100 अवैध ई-रिक्शे पकड़े जा रहे

पहले प्रतिदिन 50 रिक्शे पकड़े जा रहे थे मगर अब पिछले एक सप्ताह में प्रतिदिन 100 अवैध ई-रिक्शे पकड़े जा रहे हैं। विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ ई-रिक्शा माफिया स्क्रैप डीलरों के यहां उन्हें फिर से खरीद लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, जिसके बाद विभाग ने इन्हें स्क्रैप डीलरों के पास इन्हें कंडम करने का फैसला किया है।

शहर में 1.2 लाख पंजीकृत ई-रिक्शा हैं। जबकि जमीन पर ई-रिक्शा की वास्तविक संख्या उससे दोगुनी है।गैरपंजीकृत ई-रिक्शा में नंबर प्लेट नहीं होती है और इसलिए उनका आनलाइन चालान नहीं किया जा सकता है।ये सभी यातायात प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं और अक्सर उन सड़कों पर चलते हैं जहां उन्हें अनुमति नहीं है, जिससे यातायात धीमा हो जाता है और भीड़भाड़ होती है।परिवहन अधिकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा शिकायतें ई-रिक्शा के खिलाफ हैं।

पिछले दो साल में कितने पकड़े गए अवैध ई-रिक्शा

2023 में हुई कार्रवाई
जनवरी- से मार्च- 834
अप्रैल से जून- 61
जुलाई से सितंबर- 1227
अक्टूबर से दिसंबर- 233
2024 में हुई कार्रवाई
जनवरी से मार्च- 124
अप्रैल से जुलाई- 732
एक अगस्त से 15 अगस्त तक- 716
16 अगस्त से 21 अगस्त तक- 361
22 अगस्त से 27 अगस्त तक- 612

क्या आप मानते हैं

परिवहन विशेष न्यूज

सभी भारतीय नागरिकों और राजनैतिक दलों के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सड़क पर सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। अगर सभी राजनीतिक दल और उनके समर्थक इसका पालन करें, तो यह समाज के अन्य वर्गों को भी प्रेरित कर सकता है और सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन न करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं:

अवधारणागत दृष्टिकोण: कुछ लोगों का मानना होता है कि नियमों का पालन केवल आम नागरिकों के लिए होता है, जबकि उनके लिए विशेष छूट होनी चाहिए।

सशक्त प्रभाव: राजनीतिक दलों के समर्थक और नेताओं को कई बार सुरक्षा या अन्य कारणों से विशेष छूट मिल जाती है, जिससे वे नियमों का पालन नहीं करते।

नियमों की अवहेलना: कभी-कभी नियमों की अवहेलना या उल्लंघन की प्रवृत्ति एक आदत बन जाती है और इसका असर अन्य लोगों पर भी पड़ता है।

प्रभाव और दबाव: राजनीतिक प्रभाव और शक्ति के चलते कुछ लोगों को लगता है कि वे नियमों से ऊपर हैं, और इसलिए वे नियमों का पालन नहीं करते।

प्रशासनिक ढिलाई: कभी-कभी पुलिस और ट्रैफिक नियम लागू करने वाली एजेंसियों की कमी या ढिलाई के कारण इन नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं हो पाता।

इस समस्या को हल करने के लिए, जागरूकता बढ़ाना, सख्त नियम लागू करना और सभी को समान रूप से दंडित करने की ज़रूरत है। साथ ही, राजनीतिक दलों को भी खुद अपने समर्थकों को प्रेरित करके ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

कैलाश कॉलोनी मेट्रो से पीएनबी गीतांजलि और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से वसंत विहार तक सात दिनों तक चलेगा ट्रायल

सुषमा रानी

नईदिल्ली। 28 अगस्त केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने और प्रदूषण को मात देने की दिशा में बुधवार को एक और बड़ा कदम बढ़ाया। इसके लिए सरकार ने दो और नए रूटों पर मोहल्ला बसों का ट्रायल शुरू किया है। कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन से पीएनबी गीतांजलि और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से वसंत विहार तक इन मोहल्ला बसों का ट्रायल हो रहा है, जो सात दिनों तक चलेगा। इन मोहल्ला बसों को कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक सोमनाथ भारती एवं परमिला टोकस ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीटीसी द्वारा कैलाश कॉलोनी मेट्रो से पीएनबी गीतांजलि तक और डिम्ट्स द्वारा लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से वसंत विहार तक मोहल्ला बसों के ट्रायल का संचालन किया जाएगा। इन रूटों पर मोहल्ला बसों के संचालन से लाखों लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकेगा और लोग निजी वाहनों को छोड़ सार्वजनिक वाहनों को अपना सकेंगे। साथ ही, ये सभी इलेक्ट्रिक बसें हैं तो इनसे प्रदूषण भी नहीं होगा।

दो नए रूट्स पर मोहल्ला बसों के ट्रायल शुरू होने पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मोहल्ला बसों के ज़रिए हम स्थानीय स्तर पर सभी महत्वपूर्ण स्थानों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ रहे हैं, ताकि फ़र्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। हमने दो नए रूट्स पर मोहल्ला बसों के ट्रायल में मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, मैत्रेयी कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, एलएसआर कॉलेज, सेंट्रल स्कूल और वोकेशनल कॉलेज जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को भी ठहराव के रूप में शामिल किया है, जिससे कि आसपास रहने वाले निवासियों के साथ-साथ युवाओं और छात्रों की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। हम लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बना कर दिल्लीवासियों को कुशल और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प प्रदान कर रहें हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा दिल्लीवासी निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन को अपना सकें।

उधर, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 और मालवीय नगर के लोगों की मांग थी कि उनके लिए छोटी बसें शुरू की जाएं। आज यहां मोहल्ला बस की शुरुआत कर दी गई है। यह बस सेवा कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन से होते हुए लेडी श्रीराम कॉलेज, जीके 1 एन ब्लॉक, एम ब्लॉक मार्केट, जीके-1 ई ब्लॉक और पंपोस से होते हुए जीके मेट्रो स्टेशन, जीके 2 के सामने, चिराग दिल्ली, शेख सराय, वोकेशनल प्रेस एनक्लेव से होते हुए मालवीय नगर के गीतांजलि बस डिपो तक जाएगी। यह काफी अच्छी बस सेवा रहेगी। इसके रूट में कई मेट्रो स्टेशन, साकेत मॉल, तीन बड़े मार्केट, पीएसआरआई और मैक्स जैसे बड़े अस्पताल आते हैं। लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का धन्यवाद करता हूं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हर बड़ा टाउन प्लानर कहता है कि आपने सारी दिल्ली को मेट्रो लाइन से जोड़ दिया, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी व्यक्ति मेट्रो स्टेशन से घर कैसे जाएगा। इस वजह से लोग अक्सर दफ्तर जाने के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। मोहल्ला बसों के चालू होने से लोगों को मेट्रो स्टेशन से लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिलेगी। ये बसें पूरी तरह इलेक्ट्रिक हैं, इससे दिल्ली में प्रदूषण कम होगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन से पीएनबी गीतांजलि तक का रूट

कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन से पीएनबी गीतांजलि रूट पर चलने वाली मोहल्ला बस कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन से कैलाश कॉलोनी, एल.एस.आर. कॉलेज, सेंट्रल स्कूल, सादिक नगर, एम-ब्लॉक मार्केट जीके-1, ग्रेटर कैलाश ई-ब्लॉक, पीएस ग्रेटर कैलाश, पम्पोज़ एन्क्लेव, मस्जिद मोड़, चिराग दिल्ली, शेख सराय फेज -दो, शेख सराय मोड़, वोकेशनल कॉलेज, पी.एस.आर.आई, खिरकी गांव, हौज़ रानी, मोदी अस्पताल, प्रेस एन्क्लेव, साकेत ए-ब्लॉक, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन होते हुए पीएनबी गीतांजलि तक जाएगी।

लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से वसंत विहार तक का रूट

लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से वसंत विहार रूट पर चलने वाली मोहल्ला बस लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से रेस कोर्स, ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग, सिक्किम हाउस पंचशील रोड, ब्रिटिश स्कूल, जीसस एंड मेरी कॉलेज/मैत्रेई कॉलेज, रेलवे ऑफिसर एन्क्लेव, वेंकटेश्वर कॉलेज/सप्रिंगडेल्स स्कूल, साउथ कैम्पस, आर्यभट्ट कॉलेज/मोतीलाल नेहरू कॉलेज, राव तुला राम कॉलेज, वसंत गाँव, स्वामी मलाई मंदिर, वसंत विहार, वसंत विहार एफ-ब्लॉक, वसंत लोक होते हुए वसंत विहार मेट्रो स्टेशन तक जाएगी।

उल्लेखनीय है कि इस साल जुलाई में केजरीवाल सरकार ने प्रधान एन्क्लेव से मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से मयूर विहार फेज-तीन पेपर मार्केट रूट पर मोहल्ला बसों का परीक्षण शुरू किया था।

मोहल्ला बस 196 किलोवाट की क्षमता वाले छह बैटरी पैक से सुसज्जित है, जो 45 मिनट की चार्जिंग के साथ 200 किमी से अधिक का सफर करती है। 9 मीटर की इन मोहल्ला बसों में 23 यात्री सीटें और 13 यात्रियों के खड़े होने की क्षमता है।

आसानी से पहचान के लिए मोहल्ला बसों को हरे रंग का रखा गया है। मोहल्ला बसों में 25 फीसद सीटें (6 सीटें) गुलाबी रंग की हैं, जो विशेष रूप से महिला यात्रियों के लिए आरक्षित हैं।

मोहल्ला बस योजना का लक्ष्य 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा दिल्लीवासियों को उनके घर के आसपास फीडर बस सेवाएं प्रदान करना है। केजरीवाल सरकार का लक्ष्य 2025 तक 2,180 मोहल्ला बसें शुरू करने की है, जो विशेष रूप से सीमित सड़क चौड़ाई या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए होंगी। दिल्ली सरकार वर्तमान में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) से अधिग्रहित 100 बसों का संचालन कर रही है। इन मोहल्ला बसों की अधिकतम रूट लंबाई 10 किमी है। दिल्ली सरकार द्वारा 9-मीटर की 2,080 बसें खरीदी जा रही हैं। इसमें डीटीसी की 1,040 बसें और डिम्ट्स की 1,040 बसें शामिल हैं। ये बसें खासकर उन क्षेत्रों में संचालित होंगी, जहां 12 मीटर की बसों को परिचालन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

मोहल्ला बसों में किराया दिल्ली सरकार की एसी बसों के समान ही रहेगा। यानी 10, 15, 20 और 25 रुपए किराया होगा। महिलाएं पिंक पास के जरिए इन बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकती हैं।

मोहल्ला बसों के रख-रखाव व पार्किंग के लिए बने 16 डिपो

पूर्वी ज़ोन

गाजीपुर डिपो में 60 मोहल्ला बसें होंगी, ईस्ट विनोद नगर में 180 मोहल्ला बसें होंगी।

पश्चिम ज़ोन

द्वारका मुख्य डिपो में 40 मोहल्ला बसें होंगी, द्वारका सेक्टर 2 डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी, केशोपुर डिपो 180 मोहल्ला बसों को समायोजित करेगा, पीरागढ़ी डिपो में 135 मोहल्ला बसें होंगी, शादीपुर डिपो में 230 मोहल्ला बसें होंगी, द्वारका सेक्टर 9 डिपो में 20 मोहल्ला बसें होंगी।

दक्षिण ज़ोन

कुशक नाला डिपो में 350 मोहल्ला बसें होंगी, अंबेडकर नगर डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी।

उत्तरी ज़ोन

मुंडका डिपो में 60 मोहल्ला बसें होंगी, नांगलोई डीएमआरसी में 60 मोहल्ला बसें होंगी, नांगलोई डीटीसी डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी, रिठाला डिपो में 70 मोहल्ला बसें होंगी, कोहाट एन्क्लेव डिपो में 35 मोहल्ला बसें होंगी, नरेला बस डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी।

मोहल्ला बस योजना दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। खासकर उन इलाकों में जहां बड़ी बसों को परिचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

पेरेंट्स और बच्चे के बीच दूरियां बढ़ा देती हैं ये 8 बातें!

कई माता-पिता की ये शिकायत रहती है कि बच्चे उनसे दूर होते जा रहे हैं और घर में अलग-थलग रहना पसंद करते हैं। अगर आप भी अपने खुशमिजाज और हंसते-खेलते बच्चे को गुमसुम होता देखकर परेशान हैं या फिर ऐसी नौबत आने से पहले ही सावधान होना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है। आइए आपको इसकी 8 वजहें बताते हैं।

मां-बाप और बच्चों का रिश्ता कई बार एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है, जहां से सब धुंधला ही नजर आता है। कई बार पेरेंट्स ही जाने-अनजाने में कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, तो वहीं कई मामलों में इसके पीछे और भी कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं। जरूरी है वक्त रहते इन बढ़ती दूरियों को कम करना, जिसके लिए सबसे पहले आपको इसके पीछे की वजहें भी मालूम होनी चाहिए। खुशमिजाज और हंसी मजाक करने वाला बच्चा जब मां-बाप से दूरी बनाने लगता है, तो इसके पीछे ये 8 वजहें हो सकती हैं।

इसलिए मां-बाप से दूरी बनाने लगते हैं बच्चे

दोस्तों का असर: बच्चों की दोस्ती उन पर काफी गहरी छाप छोड़ती है। अगर बच्चे के दोस्तों का व्यवहार या विचार उससे अलग है तो वह अपने माता-पिता से अलग महसूस कर सकता है। इस कंडीशन में वह अपने दोस्तों के बहकावे में आकर अपने माता-पिता से दूरी बना सकता है।

स्कूल का प्रेशर: बच्चों के मानसिक तनाव के पीछे स्कूल का दबाव एक बड़ी वजह होता है। जब बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता या किसी कारण से तनाव महसूस करता है तो वह अपने घर में भी उसी तनाव को लेकर आता है। ऐसे में, वह माता-पिता से बात करने में हिचकिचाता है या उनसे दूरी बनाना शुरू कर देता है।

बदलता स्वभाव: जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका स्वभाव भी बदलता जाता है। इस बदलाव को समझना माता-पिता के लिए अक्सर मुश्किल होता है। जब बच्चा अपने मां-बाप के साथ बातचीत करने में अन्कम्फर्टबल महसूस करता है तो वह दूरी बना सकता है।

माता-पिता का बरताव: माता-पिता का व्यवहार भी बच्चों के बरताव पर काफी असर डालता है। अगर माता-पिता बच्चे के साथ हमेशा सख्ती से पेश आते हैं या उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो बच्चा बातचीत को कम कर सकता है।

तकनीक का प्रभाव: बच्चों का ज्यादा समय मोबाइल फोन, कंप्यूटर या अन्य गैजेट्स के साथ बीतता है, तो भी उनके व्यवहार में फर्क आ सकता है। तकनीक के साथ ज्यादा वक्त बिताने से फैमिली टाइम कम हो जाता है और मां-बाप के साथ दूरियों बढ़ने लगती हैं। यह बात बच्चों के साथ-साथ माता-पिता पर भी लागू होती है।

पर्सनल प्रॉब्लम्स: कभी-कभी बच्चों को पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं जो वह अपने माता-पिता से शेयर नहीं करना चाहते हैं। इन समस्याओं के कारण भी बच्चा अपने माता-पिता से दूरी बना सकता है।

अगर बिजी रहते हैं पेरेंट्स: माता-पिता की व्यस्तता भी बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करती है। अगर माता-पिता अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताते, तो भी बच्चा उनसे दूरी महसूस कर सकता है।

मेंटल इशूज: कुछ मामलों में बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं जो उनके व्यवहार में बदलाव ला सकती हैं। अगर बच्चा अपने माता-पिता से दूरी बना रहा है और उसके व्यवहार में अन्य असामान्यताएं भी दिख रही हैं, तो मुमकिन है कि उसे कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो।

इन कारणों के अलावा भी कई अन्य कारण हो सकते हैं जिनसे बच्चा अपने माता-पिता से दूरी बना सकता है। अगर आपका बच्चा भी आप से दूरी बना रहा है तो आपको उसके साथ खुले दिल से बात करनी करनी चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वह क्या महसूस कर रहा है। अगर आपको लगता है कि बच्चे को कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या है तो मनोवैज्ञानिक की मदद लेने में भी कोई बुराई नहीं है।

ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है पनीर भुर्जी , इस रेसिपी से मिलेगा ढाबे जैसा स्वाद

नाश्ते लंच या फिर डिनर के लिए अगर आप भी रेस्तरां स्टाइल पनीर पुर्जी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक और विभिन्न मसालों के साथ इसमें शानदार स्वाद आता है जिसे चखने के लिए बच्चों से लेकर बड़े तक बेताब रहते हैं। आइए आज आपको ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी बनाने का तरीका बताते हैं।

पनीर की भुर्जी एक ऐसी डिश है, जिसे नाश्ते से लेकर लंच या डिनर में आसानी से तैयार किया जा सकता है। आप चाहें, तो इसे रोटी के साथ खाएं या फिर ब्रेड की मदद से इसके टोस्ट तैयार करें। इसे बनाना तो आसान होता ही है, साथ ही यह बच्चों से लेकर बड़ों को भी काफी पसंद आती है। इसे और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें अलग-अलग तरह की सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं पनीर भुर्जी बनाने की आसान रेसिपी।

पनीर भुर्जी बनाने के लिए सामग्री

250 ग्राम पनीर, कद्दूकस किया हुआ
2 बड़े प्याज, बारीक कटा हुआ
2 टमाटर, बारीक कटा हुआ
1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
1 इंच अदरक, कद्दूकस किया हुआ
1/2 चम्मच हल्दी पाउडर
1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1/2 चम्मच धनिया पाउडर
1/4 चम्मच गरम मसाला
1/2 चम्मच जीरा
1/4 कप धनिया पत्ती, बारीक कटी हुई
नमक स्वादानुसार
तेल या घी

पनीर भुर्जी बनाने की विधि

पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल या घी गरम करें। फिर इसमें जीरा डालें और चटकने दें।

इसके बाद प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक डालकर सुनहरा होने तक भूनें।

फिर इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

अब इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डालकर धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकाएं।

इसके बाद स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें।

धनिया पत्ती से गार्निश करके गरमागरम सर्व करें।

जरूरी बातें

पनीर भुर्जी को आप रोटी, पराठा या नान के साथ परोस सकते हैं।

आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें अन्य सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, गाजर आदि भी डाल सकते हैं।

स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी क्रीम भी मिला सकते हैं।

अगर आप पनीर भुर्जी को ज्यादा मसालेदार बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर की मात्रा बढ़ा सकते हैं।

पनीर भुर्जी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक डिश है, जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं।

ये है बेंगलुरु के सबसे फेमस बजरंगबली मंदिर, लगती है लंबी लाइन

अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं या फिर यहां जानें की योजना बना रहे हैं तो आप हनुमान जी के इन मंदिरों का जरुर दर्शन करें। यहां मंगलवार और शनिवार को विशेष आरती और भजन-कीर्तन का आयोजन होता है। इन मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं।

नई दिल्ली। अगर आप बैंगलोर में रहते हैं या फिर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि यहां पर हनुमान जी के कई मंदिर काफी फेमस है। जहां आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हनुमान जी को शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। संकट मोचन के रुप हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी सभी के संकट दूर करते हैं और भूत-प्रेत व नकारात्मक शक्तियों से दूर करते हैं। अगर आप बैंगलोर में रहते हैं तो आप हनुमान जी के इन मंदिरों के दर्शन जरुर करें।

रागीगुड्डा श्री प्रसन्न आंजनेय स्वामी मंदिर

बेंगलुरु के उपनगर जयनगर में यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र पर मौजूद है। यहां का नजारा और भी सुंदर लगता है जब मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बता दें कि, यहां पर लोग दर्शन के साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य और शांति महसूस करते हैं। यह मंदिर काफी फेमस है, यहां पर भक्तों के लिए बैठने का स्थान, पार्किंग और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

दर्शन करने का समय

-समय- सुबह: 8:00 AM से 11:30 AM तक
-शाम: 5:00 PM से 8:30 PM तक

श्री कार्य सिद्धि अंजनेय स्वामी मंदिर बेंगलुरु में यह मंदिर आरटी नगर में स्थित है। इस मंदिर का नाम कार्य सिद्धि इसलिए भी रखा गया है, क्योंकि यहां आने वाले भक्तों का मानना है कि हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों के सभी कार्य सफल होते हैं। इस मंदिर में आने वाले भक्त नारियल बांधते हैं। नारियल बांधने की प्रथा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि माना जाता है कि नारियल बांधने से भक्तों की समस्याएं हल हो जाती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।

रोजाना ऑफिस में पहनें ट्रेंडी ऑर्गेंजा सलवार-सूट, सबकी निगाहें आप पर होगी

अगर आप भी ऑफिस में दिखना चाहते स्टाइलिश तो इन ऑर्गेंजा सूट को जरुर पहनें। अपनी बॉडी टाइप के अनुसार ही डिजाइन को चुनकर ही इन ट्रेंडी सूट को पहन सकते हैं। आप भी रोजाना ऑफिस में ऑर्गेंजा सलवार सूट पहन सकते हैं।

ऑफिस में डेली वियर पहनने के लिए हम तरह-तरह के कपड़े खरीदते ही रहते है। लेकिन ऑफिस में सबसे आरामदायक और स्टाइलिश लुक देने के लिए सलवार-सूट को पहनना पसंद किया जाता है। हालांकि, आप बाजार रेडीमेड और फैब्रिक खरीदकर कई तरह सूट डिजाइंस मिल जाएंगे। जिन्हें आप पहन सकती हैं। आप भी अपने ऑफिस में रोजाना ऑर्गेंजा सलवार-सूट के पहन सकते हैं।

फ्लोरल डिजाइन ऑर्गेंजा सलवार सूट

ऑफिस में क्लासी दिखने के लिए आप फ्लोरल पैटर्न यानी के फूलों और पत्तियों वाले डिजाइन को ही पसंद किया जाता है। इस पैटर्न में आपको कई प्रिंट वाले डिजाइंस के सलवार सूट का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा।

प्लेनडिजाइन ऑर्गेंजा सलवार-सूट

अगर आप प्लेन सूट के साथ हैवी वर्क वाले दुपट्टे को स्टाइल कर सकते हैं क्योंकि यह काफी ट्रेंडी है और इन्हें आजकल काफी पसंद किया जा रहा है। इसमें आप मोनोक्रोम कलर पैलेट के आलवा कई तरह से कलर कॉम्बिनेशन वाले सूट को स्टाइल कर सकते हैं।

फ्रॉक स्टाइल ऑर्गेंजा सलवार सूट

अगर आप कलियों वाले सूट पहनना पसंद करते हैं तो इस तरह के ऑर्गेंजा सलवार-सूट में काफी डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। आपको बाजार में फ्रॉक स्टाइल में कई सारे रेडीमेड ऑर्गेंजा सूट 1000 से 1500 रुपये तक में मिल जाएंगे।

चिकनकारी ऑर्गेंजा सलवार सूट

आजकल चिकनकारी काफी ट्रेंड में है। आप ऑफिस में चिकनकारी वाले ऑर्गेंजा सूट भी पहन सकते हैं। वहीं, इसमें डिजाइन ती बात करें तो आप पाकिस्तानी स्टाइल के सलवार-कमीज भी आपको ऑर्गेंजा फैब्रिक में देखने को मिल जाएगी।

वनप्लस के इस फोन पर 3 हजार की छूट , 100W चार्जिंग और शानदार ऑफर्स

स्मार्टफोन मार्केट में OnePlus का नाम प्रीमियम और हाई-क्वालिटी स्मार्टफोन्स के लिए जाना जाता है। OnePlus के फोन न केवल बेहतरीन डिज़ाइन और फीचर्स के लिए मशहूर हैं, बल्कि इनकी परफॉर्मेंस भी ग्राहकों को प्रभावित करती है। हाल ही में, OnePlus ने अपने एक पॉपुलर स्मार्टफोन वनप्लस नॉर्ड CE4 की कीमत में 3 हजार रुपये की कटौती की है, जिससे यह फोन अब और भी आकर्षक हो गया है।

100W चार्जिंग: नई तकनीक का चमत्कार

OnePlus के इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 100W की सुपरफास्ट चार्जिंग है। 100W की चार्जिंग क्षमता के साथ, यह फोन मिनटों में चार्ज हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और बार-बार चार्ज करने का समय नहीं निकाल पाते, तो यह फोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। केवल कुछ ही मिनटों में आप अपने फोन को इतने समय के लिए चार्ज कर सकते हैं कि दिनभर आराम से काम कर सकें।

कीमत में कटौती: अब 3 हजार रुपये सस्ता

अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की- इस फोन की कीमत में 3 हजार रुपये की कटौती की गई है। OnePlus के इस दमदार फोन की नई कीमत इसे और भी किफायती बनाती है। जिन ग्राहकों को पहले इस फोन की कीमत थोड़ी ज्यादा लग रही थी, उनके लिए अब यह एक शानदार डील हो सकती है।

एक्सचेंज ऑफर: पुराने फोन को करें अपग्रेड

अगर आपके पास पहले से एक स्मार्टफोन है और आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो OnePlus का एक्सचेंज ऑफर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस ऑफर के तहत, आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करके न वनप्लस नॉर्ड CE4 स्मार्टफोन पर अच्छी-खासी छूट प्राप्त कर सकते हैं।

क्यों खरीदें यह फोन ?

- सुपरफास्ट चार्जिंग: इसमें 5,500mAh की बैटरी है जिसे 100W सुपरवूक फास्ट चार्जर से जल्दी चार्ज किया जा सकता है। फ़ोन में 5G, 4G LTE, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4, GPS, BDS, गैलीलियो, QZSS और संचार के लिए USB टाइप-C कनेक्शन है।

- दमदार परफॉर्मेंस: वनप्लस नॉर्ड CE4 फोन में 6.7 इंच का फुल-एचडी+ (1,080 x 2,412 पिक्सल) एमोलेड डिस्प्ले है जो काफी शानदार है। यह एंड्रॉयड 14 पर आधारित ऑक्सीजनओएस 14 पर चलता है और इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। यहां डिस्प्ले HDR10+ को भी सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 सीपीयू दिया गया है। गेमिंग के लिए एक्स-एक्सिस पर एक लीनियर मोटर भी शामिल है। इसमें 256GB की इनबिल्ट मेमोरी है जिसे कार्ड के इस्तेमाल से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

- कैमरा क्वालिटी: इस फोन में दो कैमरे शामिल हैं: पीछे की तरफ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा और 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। सेल्फी लेने के लिए फोन में आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का कैमरा है।

- स्पीकर: वनप्लस नॉर्ड CE 4 के ट्विन स्टीरियो स्पीकर हाई-रेज़ ऑडियो सक्षम करते हैं।

- कीमत में कटौती: बेहतरीन सौदे की बात करें तो, इस लिंक पर क्लिक करके खरीदार OnePlus Nord CE4 को 24,999 रुपये की जगह 21,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस ऑफर प्राइस में बैंक ऑफर भी जोड़ा गया है। एक्सचेंज ऑफर के जरिए फोन खरीदने वाले ग्राहकों को 23,550 रुपये की छूट मिलेगी। लेकिन एक्सचेंज रेट के हिसाब से ऐसा लगता है कि पिछला फोन भी इसी तरह महंगा होना चाहिए था।

- कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर: इन ऑफर्स के साथ, आप इस फोन को और भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। सेल के दौरान Amazon पर कई हाई-एंड फोन बेहद कम कीमत पर उपलब्ध हैं। इस डील में Redmi, Realme, OnePlus और Poco जैसे कई मशहूर फोन उपलब्ध हैं, जिनमें से कई पर इंसेंटिव भी दिया जा रहा है।

कैसे करें खरीदारी ?

OnePlus के इस फोन को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करना पसंद करते हैं, तो OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट या अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर जाएं। वहां आपको इस फोन के सभी वैरिएंट्स और उनके डिस्काउंट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी।

समय से पहले रजोनिवृत्ति का कारण आपके जीन में है

हाल ही में हुए एक अध्ययन में महिलाओं में समय से पहले रजोनिवृत्ति के लिए जिम्मेदार जीन वेरिएंट की पहचान की गई है। यह खोज आनुवंशिक परामर्श और प्रजनन स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन में मदद कर सकती है।

हाल ही में हुए एक अध्ययन में, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीन की खोज की है जो संभवतः कई महिलाओं में समय से पहले रजोनिवृत्ति के कारण के पीछे है। यह जीन वैरिएंट जब माता-पिता दोनों से विरासत में मिलता है, तो रजोनिवृत्ति हो सकती है, वह अवधि जिसके दौरान एक महिला का मासिक धर्म चक्र लगभग एक दशक पहले ही बंद हो जाता है।

हमारे शरीर में, जीन वैरिएंट उन निर्देशों में छोटे-छोटे बदलाव होते हैं जो हमें वह बनाते हैं जो हम हैं, कभी-कभी अलग-अलग लक्षण या स्वास्थ्य स्थितियों की ओर ले जाते हैं।

नेचर जेनेटिक्स में अपने निष्कर्षों को प्रकाशित करने वाले डीकोड जेनेटिक्स के वैज्ञानिकों ने सीसीडीसी201 जीन में एक दुर्लभ आनुवंशिक वैरिएंट पर ध्यान केंद्रित किया, जो महिलाओं के रजोनिवृत्ति से गुजरने पर प्रभाव डालता है।

शोधकर्ताओं ने आइसलैंड, डेनमार्क, यूके और नॉर्वे की 1,74,000 से अधिक महिलाओं के डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि इस वैरिएंट की दो प्रतियों वाली महिलाओं, जिन्हें होमोजाइगोट्स के रूप में जाना जाता है, में रजोनिवृत्ति बहुत पहले हो जाती है, औसतन, वैरिएंट के बिना उन महिलाओं की तुलना में नौ साल पहले।

CCDC201 जीन, जिसे 2022 में मनुष्यों में प्रोटीन-कोडिंग जीन के रूप में पहचाना गया था, अंडे की कोशिकाओं में अत्यधिक सक्रिय है। अध्ययन से पता चलता है कि इस जीन के कार्य को खोने से महिला प्रजनन स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

जिन महिलाओं में इस जीन वेरिएंट की दो प्रतियाँ होती हैं, उनमें समय से पहले रजोनिवृत्ति होना आम बात है। उत्तरी यूरोपीय मूल की लगभग 10,000 महिलाओं में से 1 में यह वेरिएंट होता है, और उनमें से लगभग आधी महिलाएँ प्राथमिक डिम्बग्रंथि अपर्याप्तता का अनुभव करती हैं, जिसका अर्थ है कि वे 40 वर्ष की आयु से पहले रजोनिवृत्ति से गुज़रती हैं।

नतीजतन, इन महिलाओं के कम बच्चे होते हैं और 30 वर्ष के बाद उनके बच्चे होने की संभावना नहीं होती है। यह खोज प्राथमिक डिम्बग्रंथि अपर्याप्तता जैसी स्थितियों का अध्ययन करते समय विभिन्न आनुवंशिक कारकों पर विचार करने की आवश्यकता को उजागर करती है।

यह यह भी सुझाव देता है कि जिन महिलाओं में यह वेरिएंट होता है, उनके लिए आनुवंशिक परामर्श लाभकारी हो सकता है, जिससे उन्हें अपने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने और समय से पहले रजोनिवृत्ति के लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद मिलती है।

रजोनिवृत्ति के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए

रजोनिवृत्ति वह समय है जो किसी व्यक्ति के मासिक धर्म चक्र के अंत को चिह्नित करता है। यह प्रजनन हार्मोन की प्राकृतिक गिरावट है। इसका निदान तब किया जाता है जब आप 12 महीने तक मासिक धर्म के बिना रहते हैं, खासकर आपके 40 या 50 के दशक के दौरान।

आपके मासिक धर्म चक्र के पूरी तरह से बंद होने से पहले की अवधि पेरिमेनोपॉज़ को चिह्नित करती है, जिसमें मासिक धर्म चक्र में उतार-चढ़ाव होता है। यह रजोनिवृत्ति से 10 साल पहले हो सकता है।

जैसे-जैसे हार्मोन का स्तर गिरता है, रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं को कुछ स्वास्थ्य स्थितियों का अधिक खतरा होता है। इनमें हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और मूत्र असंयम शामिल हैं।

एस्ट्रोजन के स्तर में गिरावट कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी प्रभावित करती है, जिससे हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। रजोनिवृत्ति के बाद हड्डियों का

घनत्व कम हो जाता है, जिससे हड्डियाँ फ्रैक्चर के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।

रजोनिवृत्ति के लक्षणों को प्रबंधित करने के कई तरीके हैं। इसके अलावा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT), जीवनशैली में बदलाव जैसे कि स्वस्थ आहार बनाए रखना, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन तकनीकें मदद कर सकती हैं।

रजोनिवृत्ति का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हो सकता है। कुछ महिलाओं को इस दौरान मूड स्विंग, चिंता या अवसाद का अनुभव होता है, जो आंशिक रूप से हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है, लेकिन जीवन में होने वाले बदलावों के कारण भी होता है जो अक्सर रजोनिवृत्ति के साथ मेल खाते हैं।

विशेषज्ञ अक्सर इन भावनाओं को स्वीकार करने और सहायता लेने का सुझाव देते हैं, चाहे थेरेपी, सहायता समूहों के माध्यम से, या दोस्तों और परिवार के साथ बात करके।

Rau's IAS को कोर्ट से झटका, दोबारा कोचिंग शुरू करने की मांग हुई खारिज

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

राव आईएएस स्टडी सर्कल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में दोबारा कोचिंग इंस्टिट्यूट शुरू करने की याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई ने विरोध जताते हुए कहा कि बिल्डिंग में अभी कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं। जब तक सुरक्षा उपाय नहीं किए जाते तब तक शिक्षण संस्थान चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए...

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर राव आईएएस स्टडी सर्कल की बिल्डिंग में दोबारा कोचिंग इंस्टिट्यूट शुरू करने की याचिका खारिज कर दी। कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता ने अदालत में कोचिंग इंस्टिट्यूट दोबारा शुरू करने का आवेदन दायर करते हुए दलील दी थी कि कक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए परिसर की जरूरत है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने याचिकाकर्ता और सीबीआई की ओर से पेश अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता का आवेदन खारिज कर दिया।

मामले में गुप्ता के आवेदन पर सीबीआई ने विरोध जताते हुए दलील दी थी कि कोचिंग की इमारत में अभी कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं। जब तक इमारत में सुरक्षा उपाय नहीं किए जाते तब तक शिक्षण संस्थान चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग के सामने वाली सड़क पर वर्षा जल भरने से बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर गया था। जिससे यूपीएससी सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। बाद में बिल्डिंग को सील कर दिया गया था।

एसयूवी की जांच के लिए सीबीआई को दिया समय

अदालत ने मामले में एसयूवी चालक मनोज कथूरिया के एसयूवी को छोड़ने का निर्देश देने की मांग वाले आवेदन पर एसयूवी की जांच के लिए सीबीआई को और समय दिया। मामले की अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी। सीबीआई ने एसयूवी के निरीक्षण की स्थिति रिपोर्ट कोर्ट में दायर की थी।

रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा कि था कि आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसरों की टीम ने वाहन और इमारत के गेटों का निरीक्षण किया है। सीबीआई ने कहा आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर से इंस्पेक्शन कराया जा चुका है अब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से निरीक्षण कराना है।

दिल्ली में 100 से ज्यादा रामलीला मंचन पर संकट के बादल, पीएम मोदी तक पहुंचा मामला

राजधानी की 100 से ज्यादा रामलीलाओं के मंचन पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। रामलीला समितियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। शालीमार बाग स्थित डीडीए पार्क में पिछले 35 वर्षों से रामलीला कराती समिति के मंत्री शिवशंकर नागर निराश होकर कहते हैं कि इस वर्ष डीडीए की इस व्यवस्था से रामलीला का आयोजन असंभव है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली की 100 से अधिक रामलीलाओं के मंचन पर इस वर्ष संकटों के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि डीडीए द्वारा इससे संबंधित समितियों को इस वर्ष मात्र 10 दिनों के लिए मैदानों के आवंटन की पेशकश की जा रही है। इसी तरह डूसिब द्वारा महंगा किराया मांगने तथा एमसीडी समेत अन्य द्वारा अन्य विभागों से नए नियम से मुश्किलें भी साथ है।

अभी होती हैं 550 से ज्यादा रामलीलाएं

दिल्ली में रामलीला आयोजन का इतिहास मुगलकालीन है। मौजूदा समय में 550 से अधिक रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, उसमें 250 से अधिक मंचन खुले मैदान में होता है, जो पुरातत्व सर्वेक्षण, डीडीए, एमसीडी, डूसिब, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी व दिल्ली छावनी के अधीन आते हैं। जबकि, अधिकतर फंसे मामले डीडीए संबंधित है, जिनकी संख्या 100 से अधिक है।

मामले से जुड़े लोगों के अनुसार रामलीला आयोजन की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती है। इसके लिए अगस्त माह में मैदान की बुकिंग के साथ विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुमति लेने का क्रम शुरू हो जाता है। पितृपक्ष के पहले भूमि पूजन कर मंच समेत अन्य का निर्माण कार्य भी तेज कर दिया जाता है। पितृपक्ष 17 सितंबर से आरंभ है।

3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक होगी रामलीला

इस वर्ष रामलीला का मंचन तीन अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक है। श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार के अनुसार, मैदान के लिए डीडीए की वेबसाइट पर आवेदन करने पर 10 दिन का ही विकल्प आ रहा है। इस संबंध में वे लोग डीडीए के उच्चाधिकारियों से मुलाकात भी की, लेकिन अधिकारी उनकी समस्या समझने को तैयार नहीं हैं।

तैयारियों में चाहिए 15 से 20 दिन

रामलीला आयोजकों के अनुसार, मंचन की तैयारियों में 15 से 20 दिन लगते हैं। उसमें मंच, टेंट, कुर्सियां, प्रकाश, झूले समेत अन्य की व्यवस्था हैं। साथ ही बिना मैदान की अनुमति के दिल्ली पुलिस व अग्निशमन जैसे विभागों से आवश्यक मंजूरी नहीं मिलेगी। अर्जुन कुमार के अनुसार पिछले वर्ष जब मंजूरी संबंधित कुछ अवरोध आए थे तब उपराज्यपाल ने संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को साथ बैठाकर समस्या का निदान कराया था।

सिंगल विंडो व्यवस्था की मांग

रामलीला समितियां प्रति वर्ष विभिन्न सिविक एजेंसियों से अनुमति लेने की प्रक्रिया और नित नए नियमन को आसान कर सिंगल विंडो सिस्टम की मांग की है। ताकि, विभिन्न विभागों तक दौड़ भाग न करनी पड़े साथ ही मुश्किलें न आए।

किसी और ने आवंटित करा लिया मैदान

कुछ मामले ऐसे भी आ रहे हैं कि 10 दिनों की बुकिंग की स्थिति में रामलीला समितियों द्वारा बुकिंग नहीं कराने के बीच में कुछ अन्य लोगों ने मैदान बुक करा लिए हैं, जिससे नए प्रकार की समस्या पैदा हो गई है।

सब्जी मंडी स्थित कमला नेहरू पार्क में मंचित होते श्री नव आदर्श कला मंडल के मंचन के इस वर्ष 50 वां वर्ष है, लेकिन उनका निर्धारित मैदान किसी और नाम से बुक हो गया है।

समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव शर्मा बताते हैं कि डीडीए में उनकी समिति का पंजीयन 2026 तक है, लेकिन उन लोगों को बिना सूचित किए मैदान किसी और को आवंटित कर दिया गया है, जो शायद झूले वगैरह लगाए। ऐसे में अब वह डीडीए कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।

एसटीपी और चाट पकौड़ी लाइसेंस की मांग

इस बार, सिविक एजेंसियों द्वारा चाट पकौड़ी के लिए अलग से लाइसेंस लेने के साथ ही रामलीला समितियों से निकले वाले गंदे पानी को साफ करने के लिए एसटीपी लगाने का भी नया नियम रखा गया है, जो रामलीला समितियों की चिंता बढ़ा रहा है। इसी तरह, डूसिब द्वारा कुछ रामलीला समितियों को मैदान के लिए 50 लाख रुपये से अधिक का शुल्क मांगा जा रहा है।

लीला अवलोकन का न्यौता परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को

परिवहन विशेष न्यूज

सुषमा रानी। लालकिला ग्राउंड में आयोजित लव कुश रामलीला कमेटी का एक शिष्टमंडल कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार के नेतृत्व में केंद्रीय सड़क, परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी से मिला और उन्हें सपरिवार आगामी 03 अक्तूबर से 13 अक्टूबर तक आयोजित प्रभु श्री राम की लीला का अपनी सुविधा अनुसार किसी दिन अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया।

मंत्री महोदय ने इस आमंत्रण को तुरंत स्वीकार करते हुए शिष्टमंडल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा युग पुरुष प्रभु श्री राम की लीला हमारी युवा पीढ़ी को उनके त्याग, समर्पण, और उनके नैतिक मूल्यों से अवगत कराते हुए असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देती है, उन्होंने लीला आयोजको को बधाई देते हुए कहा आप प्रति वर्ष लीला आयोजन के दौरान पूरी दिल्ली को राममयी बना देते है। इस शिष्ट मंडल में लीला कमेटी के चेयरमैन पवन गुप्ता, महामंत्री सुभाष गोयल, संजय जैन ,संदीप भूटानी , लोकेश बंसल , राज कुमार कश्यप सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

लीला कमेटी की और से मंत्री महोदय को शक्ति का प्रतीक गदा, राम जी का चित्र और अंग वस्त्र प्रदान किया गया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने नजफगढ़ में धरने पर बैठे दिल्ली भर के किसानों को न्याय की लड़ाई में पार्टी का पूर्ण समर्थन का आश्वासन

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने दिल्ली भर के 358 गांवों के किसान जो नजफगढ़ के दौलत पुर गांव में अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठे है उनसे मुलाकात की। यादव ने किसानों को न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जमीनों के मुआवजे और सर्कल रेट दिलाने की लड़ाई में हम किसानों के साथ हैं।"

यादव ने कहा कि दौलत पुर गांव में बैठे किसान अपने कृषि उत्पादों के लिए अधिक एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा पारित भूमि अधिग्रहण अधिनियम को लागू करने, सर्कल रेट और मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से नौकरी के लिए आने वाले लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए किसानों की जमीनें सस्ते अधिग्रहित की गई थी, परंतु जिन स्थानीय लोगों की कृषि भूमि सस्ते में अधिग्रहीत की गई, उनके पास अब न तो नौकरियां हैं और न ही खेती के लिए जमीन।

यादव ने कहा कि दिल्ली में 2 से 2.5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ में जमीनें ली जाती हैं जबकि दिल्ली की सीमा के बाहर जमीन की कीमत 15 से 20 करोड़ रुपये तक है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी, उनकी भावी पीढ़ी को खेती के लिए जमीन के बिना भविष्य में रोजगार और अजीविका के संकट का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों का मुद्दा उठाने के लिए उपराज्यपाल से मिलेगी और सत्र के दौरान संसद में भी यह मामला उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग मास्टर प्लान 2041 लागू करने, मास्टर प्लान 2021 लैंड पूलिंग की संशोधित नीति लागू होने, मोटेशन शुरु करने और 74 (4) के तहत जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है।

सिख संगठनों की मांग कंगना रानौत की इमरजेंसी फिल्म पर तुरंत लगे प्रतिबंध

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली के सिख संगठनों ने पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी के साथ मिलकर कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म को सिनेमाघरों में दिखाने से रोकने के लिए एक मांग पत्र जारी किया और कहा कि सिखों की भावनाओं को देखते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.

शिरोमणि अकाली दल की महिला विंग की प्रधान बीबी रणजीत कौर ने मीडिया से बात करते हुए बताया की मांग पत्र देने आए लोगों को डीसीपी ने पूरा भरोसा दिया कि वे जल्द ही सेंसर बोर्ड को इस बारे में लिखित पत्र देंगे.

उन्होने कहा कि यह फिल्म सिख इतिहास को विकृत कर रही है और 20वीं सदी के महान सिख संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले के चरित्र और तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर पूरे सिख समुदाय को दोषी ठहराने की कोशिश की गई है और सिखों का वर्णन अलगाववादियों के रूप में किया गया है. उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि कंगना रनौत के दिल और दिमाग में सिखों के प्रति कितनी नफरत फैली हुई है.

इस फिल्म के खिलाफ पंथ के भीतर भारी गुस्सा है और देश के कई राज्यों में इसका विरोध देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि अगर यह फिल्म सिनेमाघरों में दिखाई गई तो देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है, इसलिए सरकार और फिल्म सेंसर बोर्ड को इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम सेंसर बोर्ड से अपील करते हैं कि वह इस फिल्म की रिलीज को रोकें, अन्यथा इसके परिणामों के लिए सिख समुदाय जिम्मेदार नहीं होगा. इस अवसर पर युवा नेता रमनदीप सिंह सोनू, गुरप्रीत सिंह रिंटा, अवनीत सिंह रायसन, गुरुद्वारा शिरोमणि सिख संगत के अध्यक्ष गुरुमीत सिंह, सिख स्टूडेंट फेडरेशन के अवतार सिंह मक्खन, विभिन्न गुरुद्वारा साहिबों के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में संगत मौजूद थी।

महिला डॉक्टरों के लिए नाइट ड्यूटी के नियम बदले, अस्पतालों की सुरक्षा पर चौकसी; नियुक्त होंगे मुख्य सुरक्षा अधिकारी

सुषमा रानी

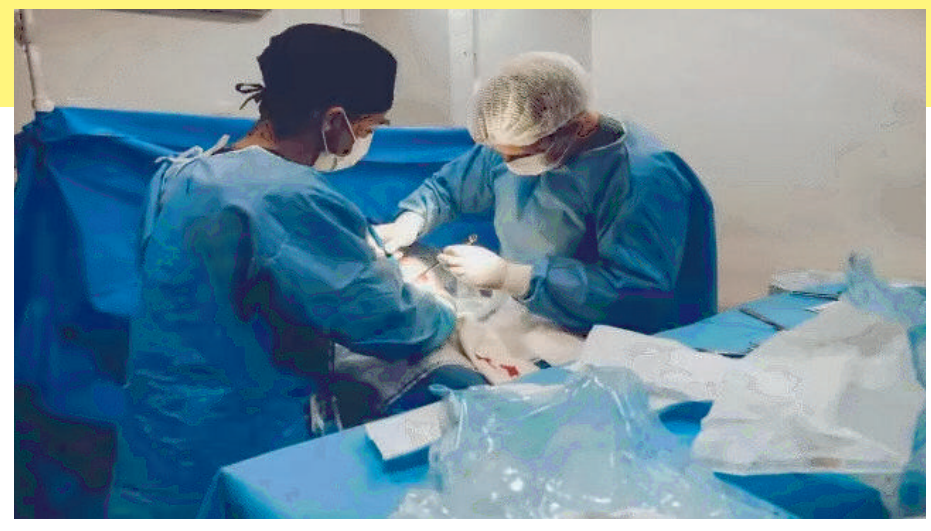

नई दिल्ली, कोलकाता डॉक्टर रेप व मर्डर केस को ध्यान में रखकर देश के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। वहां काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए वे ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में इस तरह से कई फैसले लिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन फैसलों से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों सुरक्षा के हालात में तात्कालिक सुधार में मदद मिलेगी।

स्थायी सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक उपायों पर नेशनल टास्क फोर्स विचार कर रहा है और सभी हितधारकों से सुझाव ले रहा है। बैठक में सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का डीएम और एसपी द्वारा संयुक्त सुरक्षा ऑडिट कराने का फैसला किया गया, जिसमें संबंधित संस्थान के डीन या निदेशक भी शामिल किए जाएंगे।

इसके साथ ही बड़े मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में पुलिस स्थापित करने और खासकर रात में पेट्रोलिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों ने सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के सीसीटीवी नेटवर्क की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज की कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी और उन्हें क्लाउड स्टोरेज में स्टोर किया जाएगा ताकि कोई उसे डिलीट नहीं कर सके।

स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 112

राज्य सरकारें जल्द ही इन संस्थानों में डार्क जोन की पहचान कर वहां लाइट लगाने की व्यवस्था करेगी। बैठक आम जनता की सहायता के लिए चलाए जा रहे हेल्पलाइन नंबर 112 की सेवाओं को स्वास्थ्यकर्मियों के लिए भी उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई और अधिकांश राज्य इसके लिए तैयार थे।

अस्पताल से होस्टल तक सुरक्षा एस्कोर्ट

इतना नहीं, राज्यों ने रेजिडेंट डॉक्टरों की कार्यावधि सुनियोजित करने और महिला डॉक्टर को रात के समय अस्पताल से होस्टल जाने के लिए सुरक्षा एस्कॉर्ट उपलब्ध कराने पर भी सहमति दी।

केंद्र सरकार की ओर राज्यों को स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। अभी तक 26 राज्यों ने स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बना रखे हैं।

हरियाणा की हॉट सीट पर कांग्रेस की बड़ी चुनौती, दौड़ में 22 नाम; देखिए दावेदारों की लिस्ट

परिवहन विशेष न्यूज

हरियाणा में फरीदाबाद सीट के लिए दावेदारों में से एक नाम फिक्स करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि इस सीट से कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने के लिए एक-दो नहीं बल्कि 22 लोग दौड़ में है। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए यह बड़ी चुनौती बन गई है। फिलहाल इस सीट पर भाजपा का कब्जा है।

फरीदाबाद। हॉट सीट में शामिल फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में पंजा निशान देकर किसे चुनाव मैदान में मजबूत योद्धा के रूप में उतारा जाए, यह कांग्रेस आलाकमान के लिए बड़ी उधेड़बुन बनी हुई है। आलाकमान के समक्ष दो-चार नहीं बल्कि 22 नेताओं ने टिकट पाने का दावा ठोका हुआ है।

वहीं, इसमें भी रोचक यह है कि एक ही सीट से पिता-पुत्रों की जोड़ी ने भी दावा ठोका और भतीजे ने भी। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र सीट पर अभी भाजपा का कब्जा है। वर्ष 2009 में जब यह सीट परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई तो यहां से पहला चुनाव कांग्रेस के आनंद कौशिक ने जीता था, पर 2014 में यहां से भाजपा के टिकट पर विपुल गोयल और 2019 में नरेंद्र गुप्ता ने कमल खिला दिया।

वहीं, अब कांग्रेस फिर इस सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयासरत है, पर आलाकमान के सामने चुनौती है कि जिन 22 नेताओं ने दावा ठोका हैं, उनमें चुनाव मैदान में डटने वाला मजबूत योद्धा चाहिए जो रण को जीत सके।

उधर, स्वयं को मजबूत योद्धा मानने का दावा करने वाले लखन सिंगला ने एक बार फिर से दावेदारी ठोकी है। भूपेंद्र हुड्डा गुट के नेता लखन सिंगला 2019 में यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, पर भाजपा के नरेंद्र गुप्ता के सामने चुनाव हार गए थे। अब लखन सिंगला 2014 में बल्लभगढ़ में भी कांग्रेस टिकट पर भी चुनाव लड़े, यहां वह भाजपा के मूलचंद शर्मा के सामने हार गए थे। इस तरह से उन पर दो चुनाव लड़ कर हारने का ठपा है।

कांग्रेस आलाकमान ने घोषणा कर रखी है कि दो बार चुनाव हार चुके नेताओं को टिकट नहीं देंगे, पर लखन सिंगला अपनी बात इस तरह से भी रख रहे हैं कि बल्लभगढ़ उनका क्षेत्र नहीं था, वह पार्टी के कहने पर ही वहां से उतरे थे। इसलिए उनके साथ शर्त न जोड़ी जाए।

बलजीत कौशिक से मिल रही चुनौती

उनको टिकट के सामने चुनौती प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व महासचिव बलजीत कौशिक से मिल रही है। बलजीत पूरे पांच साल तक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। सांसद कुमारी सैलजा गुट के बलजीत कौशिक पिछले दिनों यहां सफल पदयात्रा कर अपना वजूद दिखा चुके हैं। उनके पक्ष में यह बात भी जाती है कि उनके भाई आनंद कौशिक यहां से 2009 में चुनाव जीत चुके हैं, ऐसे में उनका जनाधार है।

सुमित गौड़ का भी खूंटा मजबूत

इन दोनों के साथ तीसरा मजबूत नाम सुमित गौड़ का है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रहे युवा तुर्क सुमित गौड़ विधानसभा के स्पीकर रहे कुलदीप शर्मा के भांजे हैं, उनके नाना चिरंजी लाल शर्मा करनाल से विभिन्न मौकों पर सांसद रहे हैं। उनके पक्ष में यह बात है कि वह स्वयं को किसी भी गुट का नहीं मानते हैं और अक्सर कहते रहे हैं कांग्रेस पार्टी ही उनका गुट है। सुमित गौड़ के पिता वरिष्ठ कांग्रेस नेता योगेश गौड़ ने भी आवेदन किया हुआ है।

पंजाबी चाह रहे अपने लिए टिकट

दूसरी तरफ इस सीट पर कई पंजाबी नेता भी अपना दावा ठोक रहे हैं। इनमें एडवोकेट राम कुमार मल्होत्रा, युवा नेता राजेश आर्य, पूर्व डिप्टी मेयर बसंत विरमानी, राखी सेठी, संजीव सलूजा, खुशदिल सहगल, मदन लाल आजाद के नाम प्रमुख हैं।

इन नेताओं का यह कहना है कि कांग्रेस ने पिछले दो चुनावों में फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की नौ विधानसभा सीटों पर किसी भी पंजाबी नेता को नहीं उतारा। इसी वजह से कांग्रेस हार रही है, इसलिए इस बार यहां से पंजाबी को टिकट दिया जाए।

इन सबके अलावा लोकसभा चुनाव लड़ चुके मनधीर मान, पूर्व पार्षद रोहित सिंगला, नितिन सिंगला, एडवोकेट कृष्णपाल तेवतिया, महेंद्र कौशिक, सूरज सिंह, सचिन रूपल, संचित एस कोहली, विनोद कौशिक, कवीश सलूजा व ओम प्रकाश ने भी टिकट के लिए आवेदन किया है।

हाईवे पर आग का गोला बनी कार, बाल-बाल बची चालक की जान; ऊंची-ऊंची लपटें देख सहम गए लोग

गुरुग्राम में हाईवे पर एक कार अचानक आग का गोला बन गई। इस दौरान कार चालक ने किसी तरह कार से बाहर निकल कर अपनी जान बचाई। इसके बाद उसने दमकल विभाग को आग की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल गई थी।

गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में रेलवे रोड से द्वारका एक्सप्रेस-वे जाते समय दौलताबाद फ्लाइओवर पर मंगलवार शाम पांच बजे एक कार में आग लग गई। बोनट से धुआं उठता देख कार चालक तुरंत बाहर आ गया। इसके बाद कार धूं-धूं कर जलने लगी।

वहीं, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कार रेनॉल्ट कंपनी की ट्राइबर बताई जा रही है। इस दौरान जलती कार को देखकर लोग सहम गए।

चालक ने किसी तरह बचाई जान

बताया जाता है कि एक युवक कार से द्वारका एक्सप्रेस-वे की तरफ जा रहा था। दौलताबाद फ्लाइओवर पर अचानक इंजन से धुआं निकलता दिखाई दिया। इस दौरान युवक ने तुरंत कार रोक दी और बाहर आ गया।

वहीं, देखते ही देखते आग ने पूरी कार को आगोश में ले लिया। सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीम ने आधे घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी।

दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू

जानकारी के अनुसार, आग की घटना से दौलताबाद फ्लाइओवर पर दोनों तरफ से लंबा जाम लग गया। घंटों वाहन चालक जाम में फंसे रहे। कार में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में घर बनाने का सुनहरा मौका, दीवाली पर आएगी स्कीम

अगर आप गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अपना आशियाना बनाना चाह रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) दीवाली पर आवासीय प्लॉट स्कीम निकालने की योजना पर काम कर रहा है। इससे पहले जीडीए ने ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट निकाले थे। अब इन्हें बदलकर एकल आवासीय प्लॉट कर दिया गया है। इससे प्राधिकरण को लगभग 400 करोड़ रुपये की आय मिलेगी।

गाजियाबाद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम विस्तार योजना में ग्रुप हाउसिंग के प्लॉटों के स्थान पर एकल आवासीय प्लॉट का लाभ लोगों को दीवाली पर मिलेगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास होने के बाद अब इसे धरातल पर उतारने की तैयारी हो रही है।

पिछली बार नहीं बिके थे ये प्लॉट

अक्टूबर से पहले प्लॉटों की कीमत तय कर दी जाएगी। कनावनी गांव के पास सीआईएसएफ रोड के किनारे इंदिरापुरम विस्तार योजना में 30 हजार 359 वर्ग मीटर भूमि पर ग्रुप हाउसिंग के लिए प्लॉट संख्या छह, सात और आठ बिक्री के लिए नियोजित किए गए थे।

योजना में किया गया बदलाव

यह प्लॉट बिक नहीं रहे थे। जीडीए ने प्लॉटों की बिक्री के लिए कई बार नीलामी तिथि रखी, लेकिन किसी ने प्लॉट नहीं खरीदा। जिससे इस योजना के बदलाव करने पर निर्णय लिया गया। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने इसमें बदलाव के लिए जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी के गठन का निर्देश दिया।

जीडीए को मिलेंगे 400 करोड़ रुपये

इसके बाद ग्रुप हाउसिंग को एकल आवासीय प्लॉट में बदलने का निर्णय लिया गया। इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा गया। प्रस्ताव पास होने के बाद अब दीपावली पर इस योजना को धरातल पर लाने की तैयारी हो रही है। दीवाली के बाद लोग प्लॉट खरीद सकेंगे और जीडीए की आय में इजाफा होगा। इससे जीडीए को लगभग 400 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने का अनुमान है।

उपलब्ध कराई जाएंगी ये सुविधाएं

आवासीय प्लॉटों के लिए पार्क, वर्टिकल गार्डन, सड़क, सीवर, पानी, ग्रीन बेल्ट, स्ट्रीट लाइट आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं जीडीए चारदीवारी और गेट बनवाने के बाद प्लॉटों को विक्रय करेगा। प्लॉटों के विक्रय के साथ ही लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम शुरू हो जाएगा। वहीं, इन प्लॉटों के बनने से इंदिरापुरम का और विस्तार हो जाएगा।

ग्रेटर नोएडा में गरजा बुलडोजर, कई दुकानों को किया गया ध्वस्त; भारी पुलिस फोर्स रही तैनात

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में शत्रु संपत्ति पर बनी अवैध दुकानों को जिला प्रशासन ने ढहाना शुरू कर दिया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने पहले ही दुकानों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। करीब 11 हजार वर्ग मीटर जमीन पर 187 दुकानें बनी हुई हैं। विरोध की आशंका के चलते गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी गांव में शत्रु संपत्ति पर बनी अवैध दुकानों को ढाना जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। बुधवार को जिला प्रशासन का पीला पंजा दुकानों पर चला। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया है।

प्रशासन ने पहले ही दिया था अल्टीमेटम

प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो शत्रु संपत्ति को खाली कराने में कई दिनों लग जाएंगे। शत्रु संपत्ति पर बनी दुकानों को खाली करने के लिए प्रशासन ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था। करीब 11 हजार वर्ग मीटर जमीन पर 187 दुकानें बनी हुई है। कुछ महीने पहले प्रशासन ने दुकानों को सील भी कर दिया था।

छाबनी में तब्दील हुआ शाहबेरी गांव

बावजूद इसके कुछ दुकानदारों ने दुकानों की सील को तोड़कर दोबारा अपना कारोबार शुरू कर दिया था। विरोध की संभावना को देखते हुए सुबह ही शाहबेरी गांव छाबनी में तब्दील हो गया था।

कार्रवाई के दौरान किसी तरह की विरोधाभास उत्पन्न न हो इसे देखते हुए ग्रामीणों को दुकानों के आसपास से दूर रहने के एलाउंस किया। एसीपी दो सेंट्रल राजीव गुप्ता ने बताया कि दो कंपनी पीएसी के साथ स्थानीय पुलिस कार्रवाई के दौरान मुस्तैद की गई है। शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान कई दिनों तक चलेगा।

आधुनिक तकनीक से होगी भूमिगत जलाशयों की सफाई

शहरवासियों को शुद्ध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भूमिगत जलाशय की आधुनिक तकनीक से सफाई कराएगा। प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिया है। एक महीने में कंपनी का चयन कर लिया जाएगा। अभी सामान्य और मशीन दोनों तरीके से सफाई की जाती है। तकनीक के इस्तेमाल से दुर्घटना होने का डर नहीं रहेगा। वर्तमान में यूजीआर की संख्या 14 है।

शहर के विभिन्न सेक्टरों व गांवों में 14 यूजीआर और 24 ओवर हेड टैंक की मदद से प्रतिदिन 172.50 एमएलडी भूजल की आपूर्ति की जा रही है। 45 एमएलडी गंगाजल की आपूर्ति हो रही है। निवासी आए दिन गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत करते हैं।

इस समस्या को दूर कर करने के लिए आधुनिक तरीके से सफाई कराने का निर्णय लिया है। इसके एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से शहर में शुद्ध पानी की आपूर्ति का लगातार प्रयास किया जा रहा है। नियमित निगरानी भी की जाती है। सभी यूजीआर की आधुनिक तकनीक से सफाई कराने का निर्णय लिया है। सीईओ की मंजूरी के बाद टेंडर जारी हो गया है।

छत्रपति प्रतिमा का ढहना शासन-तंत्र की भ्रष्टता का प्रमाण

ललित गर्ग

सिंधु दुर्ग में शिवाजी महाराज की इस प्रतिमा के गिर जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आना स्वाभाविक है, इससे लोगों का आहत होना भी उचित हैं। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के महानायक एवं जन-जन की आस्था के केन्द्र हैं।

मराठा पहचान और परम्परा के प्रतीक पुरुष, प्रथम हिन्दू नेता छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल ही में की गयी 35 फीट ऊंची प्रतिमा का थरथरा कर गिर जाना राष्ट्रीय शर्म एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार का दुःखद अध्याय है। इस तरह हमारे एक महानायक की महान स्मृतियों से जुड़ी इस प्रतिमा का गिरना एवं ध्वस्त होना सरकार में गहरे पैठ चुके भ्रष्टाचार, लापरवाही एवं रिश्वतखोरी को उजागर करता है। आजादी के अमृत-काल में पहुंचने के बाद भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी हमारी व्यवस्था में जिस तीव्रता से व्याप्त है, उसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है, जो सरकार की साख को धुंधला रही है, यह घटना भारतीय नौसेना की साख को भी बट्टा लगा रही है, यह घटना इसलिए भी गंभीर चिंता की बात है कि इससे हमारे सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की कलई खुल गई है। गौर कीजिए, इस प्रतिमा के निर्माण पर करीब 3,600 करोड़ रुपये की लागत आई थी और इसी 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर इसका अनावरण किया गया था।

सिंधु दुर्ग में शिवाजी महाराज की इस प्रतिमा के गिर जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आना स्वाभाविक है, इससे लोगों का आहत होना भी उचित हैं। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के महानायक एवं जन-जन की आस्था के केन्द्र हैं। वे महाराष्ट्र के जीवन का अभिन्न अंग हैं एवं वहां की राजनीति उनके नाम के इर्द-गिर्द घूमती है। महाराष्ट्र ही नहीं सम्पूर्ण देश में शिवाजी महाराज के प्रशंसक हैं। मराठों के अस्तित्व एवं अस्मिता के वे प्राण रहे हैं, मराठों को उन्होंने ने ही लड़ना सिखाया, उनके जीवन को उन्नत बनाया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के महाराष्ट्र की सभी जातियों को एक भगवा झंडे के नीचे एकत्रित किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने अपने राज्य-शासन में मानवीय नीतियां अपनाई थी जो किसी धर्म पर आधारित नहीं थी। महाराष्ट्र क्योंकि उनकी जन्मस्थली ही नहीं कर्मस्थली भी रहा इसलिए महाराष्ट्र की आबोहवा में वे आज भी जीवंत हैं। ऐसे महानायक की प्रतिमा के गिर जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है। मूर्ति का निर्माण और डिजाइन नौसेना ने तैयार किया था। कहा तो यही जा रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण प्रतिमा टूटकर गिर गई।

छत्रपति शिवाजी के महाराष्ट्र और मराठा संस्कृति के ही नहीं, बल्कि भारतीयता के प्रतीक एवं प्रेरणा पुरुष हैं। आम मराठी भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा है। ऐसे में, इस मूर्ति का ढहना राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार एवं भारतीय नौसेना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। चंद महीने बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने के कारण यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनना निश्चित है। एक मजबूत विपक्षी पार्टी शिव सेना की पूरी राजनीति शिवाजी के शौर्य व आत्म-गौरव से प्रेरित है, एनसीपी शरद पवार, कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने एकनाथ शिंदे सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और आरोप लगाया है कि छत्रपति शिवाजी का स्मारक चुनावों को देखते हुए जल्दबाजी में बनाया गया था और इस काम में गुणवत्ता को पूरी तरह से अनदेखा किया गया। प्रतिमा का ढह जाना छत्रपति शिवाजी का अपमान तो है ही और यह जाहिर है कि इसका काम घटिया गुणवत्ता का था। इसीलिये घटना को शिवाजी के अपमान के रूप में पेश किया जाने लगा है। चुनाव की सरगर्मियों के बीच शिवाजी की प्रतिमा का मुद्दा चर्चा में आ गया है। इस मुद्दे को वोट जुटाने के लिए असरदार हथियार के रूप में जरूर इस्तेमान किया जायेगा। लेकिन मूल प्रश्न है ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में कब सार्थक प्रयास होंगे? राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करके दोषियों को कड़ी सजा दिलानी चाहिए, ताकि न सिर्फ विपक्ष के आरोपों की धार को निस्तेज किया जा सके, बल्कि सार्वजनिक निर्माण में किसी किस्म की लापरवाही या उदासीनता बरतने वालों को भी यह संदेश मिल सके कि वे बख्शे नहीं जाएंगे।

यह पहली घटना नहीं है, जिसमें किसी बड़ी निर्माण योजना की कमी इस तरह की भ्रष्ट एवं लापरवाही के रूप में उजागर हुई है। हमारे सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बार-बार तार-तार होती रही है। मई 2023 में उज्जैन के महालोक कोरिडोर में लगी सप्तऋषियों की मूर्तियां भी इसी तरह आंधी-तूफान में धराशायी हो गई थीं। अयोध्या में भी सड़के ध्वस्त हो गयी थी। बिहार में एक पखवाड़े के भीतर लगभग एक दर्जन छोटे-बड़े पुलों के ध्वस्त होने की घटनाएं हैरान करने के साथ-साथ चिंतित करने वाली बनी हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल-1 पर छत गिरने की घटना से भी हर कोई हैरान हुआ है। मुंबई में घाटकोपर का होर्डिंग गिरना 14 लोगों की मौत का कारण बना था। कहीं नई बनी सड़कें धंस हो जाती हैं तो कहीं नई सरकारी इमारतों में दरारे पड़ जाती है। इन मूर्तियों, पुलों, सड़कों एवं सार्वजनिक निर्माण के अन्य सरकारी निर्माणों के ध्वस्त होने की घटनाओं ने एक बार फिर यही साबित किया है कि निर्माण कार्यों में फैले व्यापक भ्रष्टाचार और शासन तंत्र में बैठे लोगों की मिलीभगत के बीच ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी या संवेदनशीलता जैसी बातों की जगह नहीं है। आज हमारी व्यवस्था चरमरा गई है, दोषग्रस्त हो गई है। उसमें दुराग्रही इतना तेज चलते हैं कि ईमानदारी बहुत पीछे रह जाती है। जो सद्प्रयास किए जा रहे हैं, वे निष्फल हो रहे हैं। प्रतिमाएं हो या पुल-इनके गिरने से जितने पैसों की बर्बादी होती है, उसकी भरपाई आखिर किससे कराई जाएगी? जाहिर है, इनकी वजहों को समझने के लिए किसी मजबूत, पारदर्शी एवं निष्पक्ष तंत्र की जरूरत है। निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता से समझौता और राजनीतिक दबाव में जल्द से जल्द कार्य पूरा करने की प्रवृत्ति ने ऐसी दुर्घटनाओं की गति एवं मात्रा बढ़ाई है। इसके लिए समूचे तंत्र को अपनी कार्य-संस्कृति पर भी गौर करने की जरूरत है। शिवाजी की प्रतिमा के तेज हवा में यूं ढह जाने से हमें सबक सीखने की जरूरत है।

सवाल है कि जब सरकार किसी कंपनी को ऐसे राष्ट्रीय महत्व के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपती हैं, उससे पहले क्या गुणवत्ता की कसौटी पर पूरी निर्माण योजना, डिजाइन, प्रक्रिया, सामग्री, समय-सीमा और संपूर्णता को सुनिश्चित किया जाना जरूरी समझा जाता? देश में भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है, विशेषतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने देश के विकास को अवरूद्ध कर रखा है। यही कारण है कि पुल या दूसरे निर्माण-कार्यों के लिए रखे गए बजट का बड़ा हिस्सा कमीशन-रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ जाता है। इसका सीधा असर निर्माण की गुणवत्ता पर पड़ता है। निर्माण घटिया होगा तो फिर उसके धराशायी होने की आशंका भी बनी रहती है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने की पारदर्शी नीति नियामक केन्द्र बनाने के साथ उस पर अमल भी जरूरी है। विकसित देशों में भी ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि भारत में ऐसे हादसों से सबक नहीं लिया जाता। यह प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण है। विडम्बना देखिये कि ऐसे भ्रष्ट शिखरों को बचाने के लिये सरकार कितने सारे झूठ का सहारा लेती है।

रणनीति में सभी अपने को चाणक्य बताने का प्रयास करते हैं पर चन्द्रगुप्त किसी के पास नहीं है। घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए हल्ला उनके लिए राजनैतिक मुद्दा होता है, कोई नैतिक आग्रह नहीं। कारण अपने गिरेबार में तो सभी झांकते हैं वहां सभी को अपनी कमीज दागी नजर आती है, फिर भला भ्रष्टाचार से कौन निजात दिरायेगा? ऐसी व्यवस्था कब कायम होगी कि जिसे कोई "रिश्वत" छू नहीं सके, जिसको कोई "सिफारिश" प्रभावित नहीं कर सके और जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सके। ईमानदारी अभिनय करके नहीं बताई जा सकती, उसे जीना पड़ता है कथनी और करनी की समानता के स्तर तक। आवश्यकता है, राजनीति के क्षेत्र में जब हम जन मुखातिब हों तो प्रामाणिकता का बिल्ला हमारे सीने पर हो। उसे घर पर रखकर न आएं। राजनीति के क्षेत्र में हमारा कुर्ता कबीर की चादर हो। तभी इन मूर्तियों, पुलों, निर्माण कार्यों का भर-भराकर गिरना बन्द होगा।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

आगरा में लांच हुई नई इलेक्ट्रिक कार टाटा कर्व ईवी

परिवहन विशेष न्यूज

समय और बिजली की खपत कम करने के लिए टाटा मोटर्स की शानदार नई गाड़ी टाटा कर्व ईवी अब आगरा की सड़कों पर भी फर्राटा भरेगी। टाटा मोटर्स की नई गाड़ी टाटा कर्व ईवी का मंगलवार 27 अगस्त को संजय प्लेस स्थित अशोक ऑटो सेल्स में शुभारंभ हुआ। टाटा के क्षेत्रीय प्रबंधक आशुतोष तिवारी और अशोक ऑटो सेल्स की एमडी डॉ. रंजना बंसल ने इसका अनावरण और शुभारंभ किया।

टाटा के क्षेत्रीय प्रबंधक आशुतोष तिवारी ने कहा कि टाटा कर्व ईवी एसयूवी डिजाइन के युग में एक क्रांतिकारी शुरुआत है। शेप्ड टू स्टन, शेप्ड फॉर ग्रैंडियर, शेप्ड फॉर परफॉर्मेंस, शेप्ड फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और शेप्ड फॉर एब्सोल्यूट सेफ्टी के 5 प्रमुख स्तंभों के आधार पर कर्व कंपनी के मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स की एसयूवी रेंज में यह नया जोड़ एसयूवी की ताकत और कूप सुंदरता का अनूठा मिश्रण है।

टाटा कर्व ईवी तीन वैरिएंट - क्रिएटिव, एकम्प्लीश्ड और एम्पावर्ड में उपलब्ध है। यह वाहन आराम, बेहतरीन इंटीरियर फीचर्स, सुरक्षा और उन्नत तकनीक का सही मिश्रण है। इसमें लंबी रेंज और फास्ट चार्जिंग क्षमता है। सभी सुविधाएं मिड एसयूवी सेगमेंट में अन्य कंपनियों के समान कीमत पर उपलब्ध हैं।

55के डब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ आने वाली कर्व ईवी एक बार चार्ज करने पर 585 किमी की रेंज प्रदान करती है। जबकि 45के डब्ल्यूएच बैटरी पैक वाली कर्व ईवी 502 किमी की रेंज प्रदान करती है।

कंपनी के देश भर मे लगभग 9000 प्लस चार्जिंग पॉइट होंगे। उन्होने बताया कि कर्व ईवी डिजाइन, सुरक्षा और तकनीक में नई उंचाईयों को छू रही है। कर्व ईवी पैट्रोल और डीजल के कई विकल्पों के साथ आती है।

रांची में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

परिवहन विशेष न्यूज

सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के अध्यक्ष दिनेश सोनी, रांची जिला ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष अर्जुन यादव और रांची जिला ई-रिक्शा चालक संघ के संरक्षक उत्तम यादव ने कमिश्नर अंजनी कुमार मिश्रा के साथ बैठक की। सोमवार 26 अगस्त को शाम 4:00 बजे से 6:30 बजे तक ढाई घंटे तक बैठक चली। लेकिन वार्ता विफल रही। संघ के अध्यक्षों ने कहा कि उन्हें लिखित आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमने मंगलवार 27 अगस्त से इस हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया है। बैठक में आरटीए सचिव संजीव कुमार और ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली भी शामिल हुए।

झारखंड की राजधानी रांची में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों ने 27 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस हड़ताल का मुख्य कारण ट्रैफिक पुलिस और आरटीए (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) सचिव द्वारा लागू किए गए नए ट्रैफिक रूट हैं। ड्राइवरों का कहना है कि नए रूट उनके लिए बेहद असुविधाजनक हैं, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही हैं।

रांची ट्रैफिक पुलिस और आरटीए सचिव ने शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से रांची को चार जोन में बांटा है। इन जोन में ऑटो के लिए 17 और ई-रिक्शा के लिए 113 नए रूट तय किए गए हैं। चालकों का मानना है कि

ये रूट व्यावहारिक नहीं हैं और इससे उनकी आय प्रभावित होगी। इस मुद्दे को लेकर ऑटो और ई-रिक्शा चालक संघ ने कई बार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।

सोमवार 26 अगस्त को इस मुद्दे पर चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन रातू रोड से कचहरी चौक तक निकाला गया, जहां चालकों ने आरटीए सचिव और ट्रैफिक एसपी का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन के दौरान रांची जिला ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष अर्जुन यादव ने कहा, ₹हमने कई बार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो हमारे पास हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।₹

हड़ताल का असर शहर की आम दिनचर्या पर पड़ रहा है। मंगलवार 27 अगस्त की सुबह 5:00 बजे से शहर में ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन बंद कर दिया गया है। मंगलवार से 10 हजार से अधिक ऑटो और 2500 ई-रिक्शा चालक हड़ताल पर चले गए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर स्कूल जाने वाले बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ऑटो भी हड़ताल में शामिल हैं। अर्जुन यादव ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए खुद ही व्यवस्था करें, क्योंकि स्कूल ड्यूटी में लगे ऑटो भी हड़ताल में शामिल हैं।

हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है। बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने वाले ऑटो और ई-रिक्शा इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे, ताकि आपातकालीन स्थिति में लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा माल ढोने वाले ऑटो का संचालन भी सामान्य दिनों की तरह जारी रहेगा।

मारुति की सब फोर मीटर एसयूवी में ADAS सेफ्टी फीचर की हो रही टेस्टिंग, हो सकती है भारत में लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश की बड़ी वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki कुछ बेहतरीन फीचर्स को अपनी कारों और एसयूवी में ऑफर करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति अपनी सब फोर मीटर एसयूवी में ADAS जैसे सेफ्टी फीचर की टेस्टिंग कर रही है। क्या कंपनी इस फीचर को भारत में ऑफर करने की तैयारी कर रही है। इसे किस मॉडल में दिया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

ADAS की टेस्टिंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति अपनी एसयूवी में ADAS सेफ्टी फीचर की टेस्टिंग कर रही है। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे सब फोर मीटर की एसयूवी में ऑफर किया जा सकता है।

किस गाड़ी में मिल सकता है फीचर

मारुति की जिस गाड़ी में इस फीचर को टेस्ट किया जा रहा है वह सब फोर मीटर में आने वाली क्रॉस ओवर एसयूवी Maruti Fronx है। रिपोर्ट्स में जिस यूनिट की जानकारी दी जा रही है उस पर हरियाणा का टेंपरेरी नंबर लगाया गया है। साथ ही गाड़ी के फ्रंट को ढका गया है।

विदेशी मॉडल में मिलता है फीचर

मारुति की ओर से फ्रॉन्क्स एसयूवी को भारत के साथ ही कई अन्य देशों में भी ऑफर किया जाता है। हाल में ही इस एसयूवी को जापान भी एक्सपोर्ट किया गया है। जापान भेजे गए मॉडल में ADAS सहित कई अन्य सेफ्टी फीचर्स को भी दिया गया है, जिनको भारतीय बाजार में ऑफर नहीं किया जाता। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ADAS सेफ्टी फीचर वाली फ्रॉन्क्स को भले ही भारत में टेस्ट किया जा रहा है लेकिन इसे किसी और बाजार में ऑफर किया जा सकता है। अगर कंपनी इसे भारत के लिए ही टेस्ट कर रही है तो फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि इसे कब तक लॉन्च किया जाएगा।

रणबीर-आलिया, जान्हवी कपूर के साथ हार्दिक पांड्या की भी पसंदीदा गाड़ी है लेक्सस, मिलते हैं बेहतरीन फीचर्स

परिवहन विशेष न्यूज

जापानी वाहन निर्माता Lexus की ओर से भारत में कई बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन वाली एसयूवी और एमपीवी के साथ सेडान कार ऑफर की जाती हैं।

नई दिल्ली। जापान की लग्जरी वाहन निर्माता Lexus की ओर से भारतीय बाजार में कुछ समय पहले ही नई एमपीवी Lexus LM 350h को लॉन्च किया गया था। बेहद कम समय में ही यह गाड़ी बॉलीवुड स्टार और क्रिकेटर्स की पसंद बन गई है। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए जाते हैं और किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

LM 350h पसंद करने वालों में शामिल ये सितारे

लेक्सस की ओर से LM 350h को लग्जरी एमपीवी के तौर पर भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। बॉलीवुड स्टार Ranbir Kapoor-Alia Bhatt के साथ ही Jhanvi Kapoor ने भी इसे हाल में ही खरीदा है। बॉलीवुड सितारों के अलावा भारतीय क्रिकेटर Hardik Pandya के पास भी यह गाड़ी है।

बेहतरीन हैं फीचर्स

लेक्सस की ओर से LM350h में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें काले या सफेद रंग के विकल्प के साथ सीटों को चुना जा सकता है। इसके साथ ही इसमें 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एपल कार प्ले, एंड्राइड ऑटो को फ्रंट में दिया गया है। वहीं रियर में 48 इंच का बड़ा डिस्प्ले, 23 स्पीकर के साथ ऑडियो सिस्टम दिया जा रहा है। इसके अलावा इसमें फोल्डेबल टेबल, वैनिटी मिरर, छोटा फ्रिज भी दिया जाता है।

मिलता है दमदार इंजन

लेक्सस ने LM350h में 2.5 लीटर का चार सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन दिया है। जिससे एमपीवी को 192 हॉर्स पावर के साथ ही 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ गाड़ी में सीवीटी गियरबॉक्स को दिया गया है।

MPV में मिलते हैं कई सेफ्टी फीचर्स

लेक्सस की नई लग्जरी एमपीवी में कंपनी की ओर से कई बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स दिए जाते हैं। इसमें लेक्सस सेफ्टी सिस्टम, डायनैमिक रडार क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर अलर्ट, स्टेयरिंग असिस्ट, लेन ट्रेसिंग असिस्ट, ऑटोमैटिक हाईबीम, एडेप्टिव हाई बीम सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, डिजिटल इनसाइड रियर व्यू मिरर, सेफ एग्जिट असिस्ट, डोर ओपनिंग कंट्रोल, प्री-कॉलिजन सिस्टम व्हीकल डिटेक्शन जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

ऐसी गलियों में पहुंचेंगे ई-कचरा संग्रहण वाहन, जहां निगम का कचरा संग्रहण वाहन नहीं पहुंच पाता

परिवहन विशेष न्यूज

रतलाम में ऐसी कई गलियां हैं, जहां नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहन का पहुंचना मुश्किल है। अब ई-कचरा वाहन उन गलियों में पहुंचकर कचरा संग्रहण करेंगे। महापौर प्रहलाद पटेल ने नए ई-कचरा संग्रहण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही 100 हाथ कचरा गाड़ियां भी वितरित की गईं।

प्रत्येक वार्ड के लिए दो वाहन हैं। महापौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर को पूर्ण रूप से कचरा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गलियों से 100% कचरा संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा 3 नए ई-कचरा वाहन खरीदे गए हैं।

अगस्त 2024 में घट सकती है पैसेंजर व्हीकल की बिक्री, टू-व्हीलर सेल में बढ़ोतरी का अनुमान

परिवहन विशेष न्यूज

आगामी त्योहारी अवधि से पहले डीलरों द्वारा इन्वेंट्री बनाने के कारण थोक बिक्री खुदरा बिक्री से ज्यादा रहने की उम्मीद है। घरेलू बाजार में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बिक्री में लगभग तीन प्रतिशत की मामूली गिरावट आने की संभावना है। कुल मिलाकर रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2024-25 के अगस्त महीने आटोमोबाइल उद्योग की बिक्री में एक मिश्रण देखने को मिलेगा।

नई दिल्ली। अगस्त महीने में दोपहिया वाहन उद्योग की वृद्धि दर आठ प्रतिशत रहने का अनुमान है। वेल्थ और इन्वेस्टमेंट फर्म नुवामा की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में दोपहिया वाहन की बिक्री में तेजी मुख्य रूप से मजबूत ग्रामीण मांग और शहरी बिक्री से प्रेरित है। अनुकूल मानसून ने ग्रामीण भावनाओं में सुधार किया है, जिससे भी बिक्री में तेजी आई है।

त्योहारी सीजन में बढ़ेगी बिक्री

आगामी त्योहारी अवधि से पहले डीलरों द्वारा इन्वेंट्री बनाने के कारण थोक बिक्री खुदरा बिक्री से ज्यादा रहने की उम्मीद है। घरेलू बाजार में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बिक्री में लगभग तीन प्रतिशत की मामूली गिरावट आने की संभावना है।

यात्री वाहन सेगमेंट में यह सुस्त प्रदर्शन पिछले साल त्योहारी सीजन की शुरुआत की वजह से हुआ है, जिसने उच्च आधार प्रभाव पैदा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, कमर्शियल वाहन उद्योग को घरेलू बाजार में वार्षिक वृद्धि में लगभग चार प्रतिशत की मामूली गिरावट का सामना करना पड़ सकता है।

पैसेंजर व्हीकल की घट सकती है बिक्री

कुल मिलाकर रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2024-25 के अगस्त महीने आटोमोबाइल उद्योग की बिक्री में एक मिश्रण देखने को मिलेगा, जिसमें दोपहिया सेगमेंट में वृद्धि देखने को मिलेगी जबकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा।

भारत के आटोमोबाइल बाजार में दोपहिया और यात्री कारों की हिस्सेदारी क्रमशः 75.3 प्रतिशत और 17.6 प्रतिशत है। यात्री कार की बिक्री में छोटी और मध्यम आकार की कारों का दबदबा रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में एसयूवी की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है।

क्या कहते हैं आंकड़े?

पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 45,00,492 वाहनों का निर्यात किया, जिसमें से दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 76.8 प्रतिशत रही। इसी अवधि में यात्री वाहनों का निर्यात 6,62,891 यूनिट से बढ़कर 6,72,105 यूनिट पर पहुंच गया, जो 13.8 प्रतिशत की पॉजिटिव ग्रोथ दर्शाता है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2024 के अंत तक अपने आटो उद्योग के आकार को दोगुना करके 15 लाख करोड़ रुपये करना है।

ओलंपिक पदक तालिका में सैन्य किरदार

प्रताप सिंह पटियाल

एक सौ पचास करोड़ की आबादी वाले भारत में खेल प्रतिभाओं की खेल क्षमता में कमी नहीं है, लेकिन ओलंपिक जैसे वैश्विक खेल पटल पर तिरंगा फहराने के लिए खिलाडियों को खेल प्रतिभाओं के खेल हुनर का सामना करना पड़ता है'

जंग का मैदान हो या खेल का, कुश्ती का अखाड़ा हो या सियासत का, अपनी दास्तान-ए-सुजात के मजमून लिखने वाले भारतीय सेना के जवानों ने अंतरराष्ट्रीय खेलों तथा सबसे बड़े खेल महाकुंभ ओलंपिक में पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। सेना के खिलाडियों का जिक्र किए बिना भारत का खेल इतिहास अधूरा रहेगा। हिंदोस्तान की जिस महान शख्सियत की यौम-ए-पैदाइश को 29 अगस्त के दिन 'राष्ट्रीय खेल दिवस' के रूप में मनाया जाता है, वह महान हॉकी खिलाड़ी 'मेजर ध्यान चंद' एक सैनिक थे। हाल ही में फ्रांस की राजधानी 'पेरिस' में 2024 ओलंपिक का समापन हुआ है। सौ वर्ष पूर्व सन-1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन भी पेरिस में ही हुआ था, जिसमें सेना के खिलाड़ी 'दलीप सिंह ग्रेवाल' ने लंबी कूद स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ब्रिगेडियर दलीप सिंह तथा मेजर ध्यान चंद दोनों खिलाडियों का संबंध सेना की 'पंजाब रेजिमेंट' से था। भारतीय हॉकी ने ओलंपिक खेलों में आठ स्वर्ण, एक रजत व चार कांस्य सहित सर्वाधिक 13 पदक जीते हैं। सन-1928 के 'एम्सटर्डम' ओलंपिक में भारतीय हॉकी ने देश के लिए पहला 'स्वर्ण पदक' जीता था।

1928 के एम्सटर्डम ओलंपिक से लेकर 1980 के 'मॉस्को' ओलंपिक तक भारतीय हॉकी की गोल्डन गाथा में मेजर ध्यान चंद, कैप्टन रूप सिंह, ब्रिगेडियर हरचरण सिंह, कर्नल जसवंत गिल, मेजर शांता राम, कर्नल हरिपाल कौशिक, कैप्टन शंकर लक्ष्मण, ग्रुप कैप्टन रघबीर सिंह, सूबेदार हरदयाल सिंह, नंदी सिंह व वीजे पीटर जैसे सेना के दिग्गज ओलंपियन खिलाडियों का बेहद अहम योगदान था। एशियाई व कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा तीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मशहूर धावक कैप्टन 'मिल्खा सिंह' 'द फ्लाइंग सिख' ने भारतीय सेना 'ईएमई' में भर्ती होकर ही अपने खेल जीवन की शुरुआत की थी। सन-2004 के 'एथेंस' ओलंपिक में 'डबल ट्रैप स्पर्धा' में भारत के लिए एकमात्र पदक 'रजत' सेना के कर्नल 'राज्यवर्धन सिंह राठौर' 'ग्रेनेडियर्स' ने ही जीता था। हिमाचल प्रदेश के कैप्टन विजय कुमार 'डोगरा रेजिमेंट' ने 2012 के लंदन ओलंपिक में शूटिंग में 'रजत' पदक जीता था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 'जैवलिन थ्रो' में 'स्वर्ण पदक' तथा 2024 पेरिस ओलंपिक में 'रजत पदक' विजेता 'नीरज चोपड़ा' को सेना ने सन-2016 में 'राजपूताना राइफल्स' में 'जेसीओ' रैंक में कमीशन देकर उनकी खेल प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालिया पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 एथलीटों में 24 खिलाड़ी सशस्त्र बलों के थे। तीन हजार मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सूबेदार 'अविनाश सावले' तथा बॉक्सर 'अमित पंघाल' 'महार रेजिमेंट' में सेवारत हैं। सेना की महिला खिलाड़ी 'जैस्मीन लाम्बोरिया' 'बाक्सिंग' 'सीएमपी' में हवलदार है। पहलवान 'रितिका हुड्डा' 'कुश्ती' भारतीय नौसेना में सेवारत हैं। भारतीय खेलों का वो भी एक दौर था जब एशियाई व कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले कैप्टन उदय चंद, कैप्टन लीलाराम, कैप्टन मुख्तियार सिंह, सूबेदार देवी सिंह, विश्वनाथ सिंह तथा चंदगी राम जैसे सेना के दिग्गज पहलवानों ने ओलंपिक खेलों में कई देशों के पहलवानों को चुनौती पेश करके भारतीय कुश्ती का इकबाल बुलंद किया था।

भावार्थ यह है कि दशकों पूर्व जब देश गुरबत से जूझ रहा था, खिलाड़ी खेल सुविधाओं से वंचित थे, उस वक्त मेजर ध्यान चंद व बलबीर सिंह सीनियर जैसे दिग्गज खिलाडियों ने ओलंपिक महाकुंभ में हॉकी की 'गोल्डन हैट्रिक' लगाकर विश्व खेल पटल पर भारत का गौरव बढ़ाया था। वर्तमान में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाडियों को सशस्त्र बल, रेलवे तथा राज्य सरकारें भी रोजगार प्रदान कर रही हैं। सिंथेटिक ट्रैक व एस्ट्रोटर्फ जैसी आधुनिक खेल सुविधाएं मुहैया करवाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के बेहतर व महंगे विदेशी कोच भी उपलब्ध हैं। खिलाडियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध 'खेल महासंघ' स्थापित किए गए हैं। खेल उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सन-1984 में 'भारतीय खेल प्राधिकरण' की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार तथा राज्यों में खेल मंत्रालय मौजूद हैं। देश में कई निजी खेल अकादमियां खिलाडियों को प्रशिक्षित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। खेल प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विश्व की 18 प्रतिशत आबादी की हैसियत रखने वाले भारत का ओलंपिक महाकुंभ में खेल प्रदर्शन सम्मानजनक नहीं रहा है। गुरबत से जूझ रहे कीनिया, जमैका व इथोपिया जैसे देशों के खिलाडियों ने 'ट्रैक एंड फील्ड' स्पर्धाओं में अमरीका व ब्रिटेन जैसे देशों की बादशाहत को चुनौती दे डाली है। युद्ध से जूझ रहे इजरायल व यूक्रेन जैसे देशों के खिलाड़ी भी ओलंपिक में पदक जीत रहे हैं। एक सौ पचास करोड़ की आबादी वाले भारत में खेल प्रतिभाओं की खेल क्षमता में कमी नहीं है, लेकिन ओलंपिक जैसे वैश्विक खेल पटल पर तिरंगा फहराने के लिए खिलाडियों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाओं के खेल हुनर का सामना करना पड़ता है। चैंपियन बनने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी से पूरी शिद्दत, जुनून व जज्बे से जूझना पड़ता है। अतः कड़ी मेहनत, उच्च दर्जे के खेल प्रशिक्षण के साथ खिलाडियों को मानसिक तौर पर भी मजबूत होना पड़ेगा।

शारीरिक फिटनेस के साथ प्रोत्साहन, प्रेरणा व इच्छाशक्ति बहुत मायने रखते हैं। खेल मंत्रालयों व खेल संघों पर हुक्मरानी करने वाले सियासी निजाम तथा खेल व्यवस्थाओं में सेवारत सैकड़ों अहलकारों को इस विषय पर विश्लेषण करके खेलों की बेहतरी के लिए काम करना होगा। खिलाडियों के चयन, प्रशिक्षण तथा पदकवीर बनाने के लिए सेना की तर्ज पर एक उचित व्यवस्था को अमल में लाना होगा। खेल प्रतिभाओं के भविष्य के लिए सेना एक बेहतर विकल्प है। बहरहाल ब्रिगेडियर दलीप सिंह व ध्यान चंद की खेल विरासत को सेना के खिलाड़ी पूरी अकीदत से आगे बढ़ा रहे हैं, मगर सवाल वही है कि क्या हॉकी की स्वर्णिम बुनियाद के पुरोधा मेजर ध्यान चंद को 'भारत रत्न' से अलंकृत किया जाएगा? हॉकी के कुशल महारथी मेजर ध्यान चंद को भारतीय सेना नमन करती है।

संपादकीय

यहां कानून साहसी नहीं

मुख्य संसदीय सचिव शहरी विकास एवं शिक्षा आशीष बुटेल में सियासी दम है कि वह अपने विभाग के ही प्रस्ताव को कूड़े की टोकरी में तब तक सुला सकते हैं, जब तक राजनीति ऐसे गढ़े मुर्दों को बाहर न निकाले। अभी दो दिन पहले के प्रस्ताव ने जन्म भी नहीं लिया कि पालमपुर के विधायक को अपने ही विभाग पर शक हो गया। विभाग पालमपुर नगर निगम की अगली सदी को सुनिश्चित करते हुए 76 राजस्व गांवों को नगर एवं ग्राम योजना कानून के तहत लाने की रूपरेखा बनाने लगा था। यह माननीय विधायक का वादा है कि उनकी सरहद में उन्हीं के विभाग का ऐसा प्रस्ताव पर नहीं मार सकता। यह इसलिए कि जनता योजना से डरती है, अपने विस्तार और विकास से नहीं। क्योंकि जनता रूठ न जाए, इसलिए कानून बनाने वाले भी इनके कार्यान्वयन से डरते हैं। शहरी विकास है क्या, अगर इस मानसिकता को पढ़ा जाए, तो हिमाचल का हर गांव अब एक शहर है। गांव की शहर बनने की अभिलाषा में पूरा हिमाचल धड़ाधड़ निर्माण कर रहा है। हर सडक़ पर निर्माण की प्रतिस्पर्धा ने छीन लिए प्रकृति के पैगाम-प्रकृति के आयाम, घाटियां लील कर हम चबूतरे हो गए, लेकिन छत से टकराती छत को सुकून का आशियाना न मिला। अगर नवनिर्माण के औचित्य में इनसानी जरूरतों का विश्लेषण किया जाए, तो मालूम होगा कि हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रति कितने लापरवाह हैं। हम प्रदेश को अस्त-व्यस्त देखना चाहते हैं, इसलिए हमारी औकात ही नहीं कि नगर नियोजन को समझा जाए। हम शहर में रेंगना चाहते हैं, गांव में भौकाल को जगाना चाहते हैं। जाहिर है 76 राजस्व गांवों के पंचायत चुनाव बुटेल जी की सियासत में माथापच्ची बढ़ा दें या वह अनुमति दे भी दें, तो विपक्ष के हारे हुए प्रत्याशी को सहानुभूति दर्शाने का यही सुराग मिल जाए। उनके लिए पर्यटक गांव बसाना आसान हो सकता है, इसलिए कृषि विश्वविद्यालय से वह 120 हेक्टेयर जमीन ले सकते हैं। हमारे विकास के रथ अब ऐसे घोड़ों पर सवार हैं जो घास नहीं, घोषणा खाते हैं।

लिहाजा कानून से बड़ी घोषणा होनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, कानून कभी बड़ा नहीं होता है, होती है तो घोषणा ही महान। इसलिए 76 गांवों का भविष्य टीसीपी कानून तय नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके दायरे को निरस्त करने की घोषणा सहज स्वीकृत हो जाएगी। कुछ ऐसी ही घोषणाएं कानून के पर्दे हटाने के लिए काफी हैं। हम घोषणाओं में सफर करने का समाज बन चुके हैं। हम वर्षों से वन महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन बरसात के बाद वसंत को मालूम नहीं कि बहार आई किन पौधों पर। हम पार्किंग सुविधाओं की घोषणाओं पर पालमपुर को मुकर्रर करते हैं, लेकिन वाहनों के कीड़े सडक़ों पर डटे हैं। यहां कानून साहसी नहीं, बल्कि उसके सामने निडर होकर खड़े रहने वाला साहसी है। अगर ऐसा न होता तो पहाड़ यूं ही कटते नहीं, खड्डें रेत को तरसती नहीं और घर की नींव तक पहुंचे माफिया के सामने हम बिकते नहीं। हमारी घोषणाएं नए भवन, नई इमारतें और नए कार्यालय खोल सकती हैं, लेकिन सेल्फी प्वाइंट पर उगी घास हम नहीं उखाड़ सकते। लावारिस गोवंश अगर डीसी कार्यालयों तक पहुंच कर भी आवारा घोषित नहीं, तो कमाल का सुशासन हमारी आंखों के सामने दौड़ता है। वन वे ट्रैफिक रूल को तोडने वालों के साहस को दुहाई दें या बढ़ते पुलिस जिलों के मुखियाओं को सलाम कर दें। दिल तो करता है कानून की अतिक्रमित बस्ती में बसा जाए, हमारे हुक्मरानों को सिर्फ यह इत्तिला दे दी जाए। आश्चर्य यह कि अगर विधायक शहरी विकास योजनाओं के प्रारूप में इस तरह का रवैया पाले रहेंगे, तो पालमपुर जैसे शहरों में नगर निगम की स्थापना का औचित्य क्या। यहां योल कैंप का उदाहरण भी दिया जा सकता है जहां दशकों बाद छावनी बोर्ड से मुक्त होकर शहर के लोगों ने गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की है, नतीजतन गंदगी और अतिक्रमण के आलम में विकृतियां पैदा हो गई हैं। यदि योल छावनी के शहरी क्षेत्र को धर्मशाला नगर निगम में समाहित कर दें, तो ब्रिटिश काल से शुरू हुई शहरी परिकल्पना में सुनियोजित विकास की निरंतरता जारी रह सकती है। राजनीति के स्वार्थों में फंसा हिमाचल कब एक सुनियोजित मॉडल के तहत भविष्य के विभिन्न पहलुओं का संरक्षण करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है।

राय

'जातिवाद' का अनर्गल अलाप

मिस इंडिया, बॉलीवुड, ओलंपिक खिलाड़ी एवं क्रिकेटर, उद्योगपति, मीडिया और न्यायपालिका आदि में आरक्षण लागू नहीं होता। इन क्षेत्रों का सरकार और आरक्षण से क्या लेना-देना है? वे अधिकतर गैर-सरकारी क्षेत्र हैं। नौकरशाही और सरकारी न्यायपालिका में आरक्षण कुछ हद तक लागू होता है। 'मिस इंडिया' सौंदर्य, फैशन और बौद्धिकता के संगम का खुला मंच है। यदि दलित, आदिवासी, पिछड़े ऐसी प्रतियोगिताओं में शामिल होना चाहते हैं, तो एक दिन 'मिस इंडिया' ही नहीं, 'मिस वर्ल्ड' और 'मिस यूनिवर्स' के ताज भी पहन सकती हैं। रीता फारिया पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं, जिन्होंने 1966 में 'मिस वर्ल्ड' का खिताब जीता था। वह सवर्ण नहीं थीं, बल्कि घोर अल्पसंख्यक 'पारसी' समुदाय की थीं। इस समुदाय की आबादी आज भी एक लाख से कम है। किसी ने आज तक सवाल नहीं किया कि रीता ने ऐसी अभूतपूर्व और अंतरराष्ट्रीय सफलता कैसे अर्जित की? ओलंपिक पदक विजेता हॉकी टीम में अक्सर सिख और जाट समुदाय के खिलाड़ी ज्यादा खेलते हैं। वे अल्पसंख्यक और ओबीसी हैं। ओडिशा के आदिवासी खिलाडियों ने भी ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय हॉकी खेली है। दुनिया उनके बेमिसाल खेल को जानती है। उन्हें दलित, ओबीसी, आदिवासी के आधार पर टीम में शामिल नहीं किया गया। वे सक्षम, बेजोड़ खिलाड़ी रहे हैं, लिहाजा भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बॉलीवुड रचनात्मक चेहरों का विशाल और व्यापक समंदर है। रचनात्मक प्रतिभा बड़ी दुर्लभ होती है। किसी को आरक्षण के जरिए अभिनेता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार, कैमरामैन आदि नहीं बनाया जा सकता। अलबत्ता लगातार अभ्यास और प्रशिक्षण से प्रतिभाएं निखर भी उठती हैं।

एनएसडी और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट इसके विरले उदाहरण हैं। बॉलीवुड के समंदर में दलित, पिछड़े, आदिवासी भी होंगे! राहुल गांधी कैसे दावा कर सकते हैं कि वहां इन जातियों के चेहरे नहीं हैं? मीडिया का हुनर और रचनात्मक कौशल भी भिन्न है। हर आदमी यह काम नहीं कर सकता। जोखिमों से खेलना पड़ता है और एक अच्छा लेखक भी बुनियादी कुशलता है। हम असंख्य दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जानते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय मीडिया में बुलंदियां छुई हैं। उनमें कुछ संपादक भी रहे हैं। उद्योगपति ऐसे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें औद्योगिक साम्राज्य विरासत में मिले हैं और उन्होंने अपने ज्ञान, मार्केटिंग, मेहनत, निवेश से अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। कइयों ने निजी प्रयास से औद्योगिक कंपनियां स्थापित की हैं। उद्योग निजी क्षेत्र है, जिसमें आबादी के अनुपात के आधार पर आरक्षण नहीं है और न ही दिया जा सकता है। दलित, पिछड़े, आदिवासी जो प्रगति कर चुके हैं और शहरों में अच्छी नौकरी करते हैं, वे शेयर बाजार में अच्छा-खासा निवेश करते हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। राहुल गांधी की 'रिसर्च टीम' ने उन्हें ऐसे तथ्य नहीं बताए। सवाल है कि क्या किसी को आरक्षण के आधार पर उद्योगपति या किसान तक भी बनाया जा सकता है? कदापि नहीं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आजकल 'जातीय जनगणना' का जुनून सवार है। वे सिर्फ 70 फीसदी या 90 फीसदी आबादी की भागीदारी की बात कर सकते हैं। कांग्रेस ने तो करीब 55 साल देश पर शासन किया है। तब उसने 'जातीय भागीदारी' को सुनिश्चित क्यों नहीं किया? राहुल और अखिलेश से ही पूछ लिया जाए कि यदि देश में 'जातीय जनगणना' करवा ली जाए, तो आप उसे क्रियान्वित कैसे करेंगे? आजकल 'जातीय अनर्गल अलाप' करना खासकर उन दोनों की राजनीति है। यह सोच और नीति निजी क्षेत्र या निजी प्रतिभा, निजी निवेश और अनुसंधान पर लागू कैसे हो सकती है?

सजा बढ़ाने से नहीं रुकेंगी रेप की घटनाएं

लक्ष्मीकांता चावला

क्या इस देश में डांस बार में महिलाओं को नचाना जरूरी है? अगर डांस ही देखना है तो क्या शराब पिलाना जरूरी है? विवाह-शादियों में शराब जैसा जहर पिलाना ही है तो क्या उसे पिलाने के लिए लड़कियां ही चाहिए और लड़कियां भी वे जिन्हें आधे-अधूरे वस्त्रों में वहां लाया जाता है'

मैं अपने भारत देश की बात कर रही हूं। हमारा मंत्र है : 'मातृवत परदारेषु'। हम मां को प्रथम आचार्य मानते हैं और प्रथम गुरु भी। वर्ष में दो बार कन्या पूजन करते हैं और रक्षाबंधन भी सांस्कृतिक त्योहार है। कोई भी शुभ कार्य करना हो तो पहले कन्या पूजन करते हैं। वैष्णो देवी के दरबार में सुबह-शाम की आरती के बाद किस प्रकार कंजकों अर्थात बच्चियों का पूजन होता है और देखने वाले कितनी श्रद्धा से देखते हैं, यह भी पूरा देश जानता है। फिर भी उसी भारत देश के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो यह आंकड़े दे रहा है कि भारत में एक दिन में औसतन 87 बलात्कार की घटनाएं होती हैं। अंग्रेजी में रेप कह देते हैंए शायद वास्तविकता को छिपाने के लिए। इसके साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा दी जानकारी के अनुसार एक दिन में पांच और छह के लगभग महिलाएं, बालिकाएं दरिंदगी का शिकार होती हैं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्षों के मुकाबले रेप के मामलों में 13.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह स्वयं में ही लज्जाजनक समाचार है। व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र के लिए भी शर्म की बात है। ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश के बाद दिल्ली में ऐसी घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं।

केवल अगस्त के महीने में दक्षिण, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम भारत के सभी भागों में भारत की बेटियां बलात्कार का शिकार हुईं। बंगाल के कलकत्ता में डाक्टर के साथ अस्पताल परिसर में ही जो दरिंदगी हुई, उसके लिए पूरे देश का डाक्टर आंदोलन कर रहा है, सुरक्षा की मांग कर रहा है। पीड़िता के लिए न्याय की बात कही जा रही है और इस हड़ताल के कारण देश के गरीब ही दुखी हुए। बेटी को न्याय मिले, सब चाहते हैं, पर गरीब के बच्चे अस्पताल की दहलीज से बिना इलाज करवाकर तड़पते वापस आ जाएं, यह कोई नहीं चाहता। मेरा एक प्रश्न है कि जो गुस्सा, जो विरोध प्रदर्शन, जो राजनीतिक दूषणबाजी बंगाल की डाक्टर के लिए हो रही है, उसके शोर में हमारे नेता, पक्ष और विपक्ष के सत्तापति उन दुर्घटनाओं को क्यों नहीं देख-सुन रहे जहां एक दर्जन से ज्यादा बेटियां इस कामवासना के अंधे पुरुषों की पशुवृत्ति का शिकार हुईं। कहीं यह कोई राजनीतिक हित की पूर्ति तो नहीं हो रही? यह तो एकदम ताजी घटना है कि ठाणा जिला महाराष्ट्र के एक स्कूल में स्कूल के ही कर्मचारियों ने दो बच्चियों के साथ यौन शोषण का अपराध किया। जैसे ही माता-पिता को पता चला, पुलिस भी हरकत में आई। अपराधी गिरफ्तार भी हो गया, लेकिन दो दिन पहले वहां ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसमें स्कूल भवन भी तोड़ दिया गया, रेल ट्रैक जाम कर दिया, हजारों व्यक्ति क्रोध से उबलते हुए सडक़ों पर आए। पुलिस से टकराव भी हो गया। गुस्सा होना ही चाहिए। बेटियों के साथ इस पशुवृत्ति को रोकना ही होगा, पर आखिर कब तक यह सब होता रहेगा? इसी सप्ताह पंजाब की एक लडक़ी क्यों और कैसे उत्तराखंड के देहरादून में एक बस में शायद रात के समय पहुंची और बस के ड्राइवर, कंडक्टर आदि पांच पुरुषों की शिकार हुई। ऐसी जानकारी मिली है कि उसकी आयु से कई वर्ष बड़े वे बलात्कारी थे। उसके पिता की आयु से भी बड़े, बड़े भाई से भी बड़े।

एक व्यक्ति तो 57 वर्ष की आयु का था और सबसे छोटा 34 वर्ष का। अब प्रश्न यह है कि क्या लडक़ी उन्हें अपनी वासनापूर्ति का साधन दिखाई देती है? उसको संरक्षण देने की बात, उसे उसके ठिकाने पहुंचाने की बात किसी के मन में नहीं आती? आखिर ऐसी अपराध वृत्ति देश के इन पुरुषों में क्यों पैदा हो गई? एक नहीं अनेक घटनाएं अगस्त की हैं। बैंगलोर के एडीशनल पुलिस कमिश्नर रमन गुप्ता ने भी बताया कि एक लडक़ी जो रात को घर लौट रही थी, वह किसी से लिफ्ट मांगने का अपराध कर बैठी और फिर लूटी गई। तमिलनाडु के एक स्कूल में नाबालिग छात्राओं के साथ यौन उत्पीडऩ किया गया। एक छात्रा के साथ यौन शोषण भी हुआ। यह सारा दुष्कर्म एक फर्जी एनसीसी कैंप के दौरान किया गया। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के त्रिची में दस वर्षीय मासूम का यौन शोषण हुआ। राजस्थान के जोधपुर से तीन वर्षीय बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। कूड़ा बीनने वाले परिवार की बच्ची उठाकर ले गए और अपनी हवस का शिकार बनाया। अभी ताजी घटना है। अमृतसर के एक होटल में लुधियाना से लाई गई बच्ची की भी यही किस्मत रही। यह ठीक है कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी भी हो गई, पर जो चोट इन बेटियों को सहनी पड़ी, उसका उपचार कभी नहीं हो सकेगा। घटनाएं तो इस समय भी हो रही होंगी, जब यह संदेश लिखा जा रहा है देश को पहुंचाने के लिए, पर इसका हल क्या है? जो समर्थ लोग हैं, उन्हें अपना रंग-ढंग बदलना होगा। यहां फैशन मेले होते हैं। अधिकतर वस्त्र आभूषण के प्रदर्शन के लिए नहीं, महिलाओं के अर्धनग्न शरीरों का प्रदर्शन किया जाता है। अमीरों का बदनुमा रिवाज चल पड़ा, विवाह-शादियों में शराब पिलाने के लिए देशी-विदेशी लड़कियों को किराए पर लिया जाता है। तथाकथित स्पा सेंटरों में थाईलैंड तक की लड़कियां पंजाब में कितनी पहुंच चुकी हैं, सरकार को भी पता नहीं। जैसे अमृतसर में स्पा सेंटर पकड़ा गया, लड़कियां हाथ में आ गईं। जो बड़े बड़े ग्राहक थे, वे न कानून को दिखाई दिए, न समाज को, क्योंकि वे पैसे वाले थे। मुंबई जैसे महानगरों के डांस बार में डांस देखने कितने लोग जाते हैं।

वे उनके हाव-भाव, अश्लील इशारे देखने और करने के लिए उन पर नोट उड़ाते हैं। कामुकता को ही बढ़ावा देते हैं और महिलाओं के शरीर इस तरह खरीदे जाते हैं। मुझे लगता है कि हमने बहुत महिला दिवस मना लिए। बाल दिवस, पिता दिवस, माता दिवस, चाकलेट दिवस, वेलेंटाइन डे, बहुत कुछ मना लिया। अब देश में पुरुष दिवस मनाना चाहिए। वर्ष में एक बार नहीं, हर महीने। उस दिन हर घर की महिला अपने पुत्र, पिता, पति, भाई आदि सभी पुरुष रिश्तेदारों से यह संकल्प ले कि देश की हर बेटी को अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी मां के रूप में ही देखेंगे। फैशन मेलों में उनके शरीर पर नोट उड़ाने नहीं जाएंगे। डांस बार में शराब के साथ शबाब के नजारे नहीं लेंगे। अगर दुर्गा पूजन व कन्या पूजन करना ही है तो दुनिया की किसी भी बेटी को न अश्लील शब्द कहेंगे, न कुदृष्टि डालेंगे। यह भी समझाना होगा कि जो गालियां वे निकालते हैं, वे गालियां महिलाओं की शालीनता के विरुद्ध हैं, उनका अपमान करने वाली हैं।

मुझे तो सरकारों की अक्ल पर कभी-कभी रोना आता है कि जो जाति के लिए अपमानजनक शब्द कहने पर कानून पकड़ता है, वही कानून महिला सूचक गालियां निकालने के लिए इन पुरुषों को क्यों नहीं पकड़ता? क्या इस देश में डांस बार में महिलाओं को नचाना जरूरी है? अगर डांस ही देखना है तो क्या शराब पिलाना जरूरी है? विवाह शादियों में शराब जैसा जहर पिलाना ही है तो क्या उसे पिलाने के लिए लड़कियां ही चाहिए और लड़कियां भी वे जिन्हें आधे अधूरे वस्त्रों में वहां लाया जाता है। आखिर किस किताब में यह लिखा है कि शरीर पर मालिश करने के लिए देशी-विदेशी लड़कियां ही चाहिए। जब पुरुषों के लिए मालिश करने वाली लड़कियां लाई जाती हैं तो इसका सीधा अर्थ यही है कि यह उनका कामुकता को शांत करने का नहीं, बल्कि और भडक़ाने का एक ढंग है। क्या भारत सरकार बता सकती है कि पूरे देश के स्पा सेंटरों या डांस बार या विवाह-शादियों में शराब पिलाने के लिए विदेशों से कितनी लड़कियां देश में लाई गई हैं? ऐसे कौनसे गिरोह हैं जो इन लड़कियों को लाते हैं और फिर वही हालत होती है जो अमृतसर के स्पा सेंटर में थाईलैंड की लड़कियां छत से कूदीं।

जनों में जन, पशुजन

मैं अपने मुहल्ले की पल पल की अपने घर से लेटा ही खबर रखने का हुनर रखता हूं। मुहल्ले की ऐसी कोई हरकत नहीं जिसकी मुझे खबर न हो। इसलिए समझदार मुहल्ले वाले मुझे मुहल्ले का खबरूद्दीन भी कहते हैं। मुहल्ले को जिस खबर की जरा सी भी खबर नहीं होती, मुझे उसकी खबर से अधिक होती है। कल मुहल्ले में जैसे ही मास्साब ने इंट्री मारी और मरियल से मरियल कुत्ते भौंकने लगे तो मैं तुरंत जान गया कि मुहल्ले में कोई गलत आदमी प्रवेश कर गया है। अब पता नहीं कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं कि जब भी मुहल्ले में गलत नियत का बंदा प्रवेश करता है कि मरियल से मरियल कुत्ता भी भौंकना शुरू कर देता है। अबके फिर कुत्तों का भौंकना सही निकला। देखा तो मास्टर जी कंधे पर झोला लटकाए सामने। राम सलाम के बाद मैंने मास्टर जी से पूछा, 'मास्साब! आज फिर स्कूल के बदले यहां?' उन्हें आता देख उनकी बिरादरी की कृपा से बारह पास बीवी ने सुबह की बची चाय उनके लिए कप में डाली। 'क्या करें भाई साहब! सरकार ने कंधे पर गणना का ऐसा झोला लटका दिया है कि'।' 'तो अबके किसकी गिनती आए हैं जनाब? लकड़बग्घों की?' 'नहीं भाई साहब! जबसे पशु आदमियों के साथ रहते सुधरने लगे हैं और आदमी पशुओं के साथ रहते पशु बनने लगे हैं, तबसे जन तो कोई सोसाइटी से लेकर सिविल सोसाइटी तक में रहे नहीं। अब तो जहां देखो, बस पशुजन ही पशुजन! इसलिए पशु विभाग को पशुजन की गणना करवानी पड़ रही है।' 'पशुजन बोले तो?' मैं अवाक। अब ये पशुजन कहां से आ गए किस्म किस्म के जनों के बीच? 'पशुजन बोले तो दो पैरों पर चलने वाला जंतु जिसका दिमाग उसकी खोपड़ी की बजाय उसके पैरों में होता है। जिसके सड़े दिमाग पर लाख पेस्टिसाइड डालने के बाद भी ऐसे वैसे कीड़े पड़ जाते हैं जो अड़ोस पड़ोस को नरक बना कर रख देते हैं।' उन्होंने अरस्तू होते कहा तो मेरे स्वस्थ दिमाग में सहसा कीड़े कुलबुलाने लगे, पर मैंने उन्हें जैसे कैसे दबाकर रखा। 'माफ करना! पूछना है तो गलत सा, पर आप बता सकते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस में मुहल्ले में कितने पशुजन हैं? असल में पड़ोसियों को अपने बारे में उतना सटीक पता नहीं होता जितना उनके पड़ोसियों को उनकी रग रग का होता है।'

'पशुजन बोले तो?' 'यही कि आदमी होते हुए भी आपके घर में, आदर्श अड़ोस पड़ोस में कितने सांड हैं। यही कि आदमी होते हुए भी आपके घर में, आदर्श अड़ोस पड़ोस में कितने गधे हैं। यही कि आदमी होते हुए भी आपके घर में, अड़ोस पड़ोस में कितने टट्टू हैं। यही कि आदमी होते हुए भी आपके घर में, अड़ोस पड़ोस में कितने कुत्ते वैगरह हैं। यही कि आदमी होते हुए भी आपके घर में, अड़ोस पड़ोस में कितने सियार हैं। यही कि आदमी होते हुए भी आपके घर में, अड़ोस पड़ोस में कितने भेड़िए हैं। यही कि आदमी होते हुए भी आपके घर में, अड़ोस पड़ोस में कितने' ।' 'मतलब तुम ये गिनने आए हो कि आदमी होते हुए भी कितने पशु हैं?' 'जी!' अगर सबसे पहले अपने घर के पशुजन के बारे में बताएं तो कहते मास्साब ने अपना रजिस्टर खोला तो मैंने कहा, 'देखो बंधु! अब आपसे छिपाना क्या! सरकार के पास और कुछ सही हो या न, पर आंकड़े तो कम से कम सही होने चाहिए ताकि विकास अबाध गति से रुका रहे।' 'तो ऐसा करो, मेरा बेटा तो सांड है। सारा दिन बाजार में आवारा घूमता रहता है। कभी इसे सींग मारता तो कभी उसे। उसे कोई पूछने वाला नहीं। मैं भी नहीं। और बीवी! समझ नहीं आ रहा उसे किस पशुजन श्रेणी में रखूं? उसे पशुजन की हर श्रेणी में लिख लो। रही बात मेरी तो मुझे आप गधे की श्रेणी में रख सकते हैं। जबसे विवाह हुआ है, घर का एक एक बोझ चुपचाप अपनी पीठ पर ढो रहा हूं। किसी को इस बात से कोई लेना-देना नहीं कि मैं हंस रहा हूं कि रो रहा हूं।' 'और आपके पड़ोस में?' उन्होंने पूछा तो मैंने बिन सोचे कहा, 'आजू वाले पड़ोस में दो भैंसे, दो सांड और दो गधे रहते हैं। बाजू वाले हरि निवास में एक लोमड़, एक लोमड़ी, एक एक बिल्ला निश्चिंत लिख लीजिए। बेटा किसी गैंडे से कम नहीं। इतनी मोटी चमड़ी का कि लाख समझाओ, क्या मजाल जो समझ जाए। और उससे अगले पड़ोस में बस एक ही रहते हैं। उन्हें ऊंट की कैटेगिरी में लिख लीजिए। जब देखो ऊंट की तरह पूरे के पूरे अकड़े हुए'।' अब मास्साब की चाय भी खत्म हो गई थी और मुझसे काम भी। उन्होंने सादर हाथ जोड़े और अगली हवेलियों की ओर पशुजन गणना का झोला कंधे पर उठाए दुम मटकाते खिसक लिए।

होम लोन लेने से पहले समझें दोनों के अंतर, फायदे-नुकसान जानने के बाद लें फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

होम लोन लेते समय हमें फिक्स्ड रेट (फ़िक्स्ड रेट) और फ्लोटिंग रेट (फ्लोटिंग रेट) में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। यह दोनों ऑप्शन का कनेक्शन भले ही ब्याज दर (इंटरेस्ट रेट) से है पर इनके बीच काफी अंतर है। ऐसे में इस आर्टिकल में हम आपको इन दोनों ऑप्शन के अंतर के साथ इनके फायदे व नुकसान के बारे में बताएंगे।

नई दिल्ली। अपना घर का सपना हर कोई देखता है। इस सपने को साकार करने में होम लोन (Home Loan) अहम भूमिका निभाता है। होम लोन के जरिये आप अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। जब भी बैंक या वित्तीय संस्थान में आप लोन लेने जाते हैं तो आपको फिक्स्ड रेट (Fixed Rate) और फ्लोटिंग रेट (Floating Rate) में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है।

होम लोन में इंटरेस्ट चुकाने के लिए दिए जाने वाले इस ऑप्शन में से हमें कौन-सा सेलेक्ट करना चाहिए। इन दोनों के फायदे नुकसान को जान लेने के बाद ही हमको कोई फैसला लेना चाहिए। हम आपको इस लेख में इन दोनों के अंतर (Fixed vs Floating Rate) के साथ फायदे-नुकसान के बारे में बताएंगे।

फिक्स्ड रेट (Fixed Rate)

फिक्स्ड रेट ही समझ आता है कि लोन की पूरे टेन्योर तक ब्याज दर (Interest Rate) एक समान रहेगी। ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा ईएमआई (EMI) भी नहीं बदलेगी।

इसे ऐसे समझिए कि अगर आपने कोई होम लोन 8.20 फीसदी की दर से 30 साल के लिए लिया है जिसमें मासिक ईएमआई 22,000 रुपये बन रही है। ऐसे में 30 साल तक आपको मासिक 22,000 रुपये की ईएमआई देनी होगी, यानी ईएमआई में 30 साल तक कोई बदलाव नहीं होगा।

आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि कई बैंक कुछ समय के बाद फिक्स्ड रेट को फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको होम लोन लेने से पहले इससे जुड़ी बातों को पहले कन्फर्म कर लेना चाहिए।

फ्लोटिंग रेट (Floating Rate)

फ्लोटिंग रेट में ब्याज दर में बदलाव होता रहता है। इसमें ब्याज दर बैंक के बेंचमार्क की दरों के साथ अलाइन होती है। ऐसे में जब भी भारती रिजर्व बैंक (RBI) रेपो रेट (Repo Rate) में कोई बदलाव करता है तो होम लोन की ब्याज दरों में बदलाव होता है। ब्याज दरों में बदलाव के साथ ही ईएमआई भी बदल जाती है। अगर ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है पर आप ईएमआई नहीं बढ़वाना चाहते हैं तो लोन की अवधि बढ़ जाती है।

क्या है फायदे और नुकसान

- फिक्स्ड रेट में लोन की ईएमआई तय रहती है, जिससे लंबे समय तक आपके मनी फ्लो पर कोई असर नहीं पड़ता है।
- फ्लोटिंग रेट में ब्याज दर के बढ़ जाने से लोन की ईएमआई भी बढ़ सकती है। इसका असर आपके सेविंग और बजट पर पड़ता है।

फ्लोटिंग रेट में लोन की अवधि बढ़ जाने की वजह से या फिर ईएमआई बढ़ने से परेशानी हो सकती है। वहीं फिक्स्ड रेट में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि, अगर बेंचमार्क रेट में गिरावट होती है तब भी इसका लाभ नहीं मिलता है।

SEBI के एक्शन के बाद धड़ाम से गिरे शुगर कंपनी के शेयर, 14 फीसदी से ज्यादा फिसला स्टॉक

आज राणा शुगर्स के शेयरों में बिकवाली आई। सेबी (SEBI) के एक्शन के बाद निवेशक शेयर को बेच रहे हैं। सेबी ने कंपनी के प्रमोटरों और कुछ अधिकारियों को शेयर मार्केट से 2 साल के बैन कर दिया है और जुर्माना लगाया। यह फैसला फंड्स की हेराफेरी के बाद लिया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर...

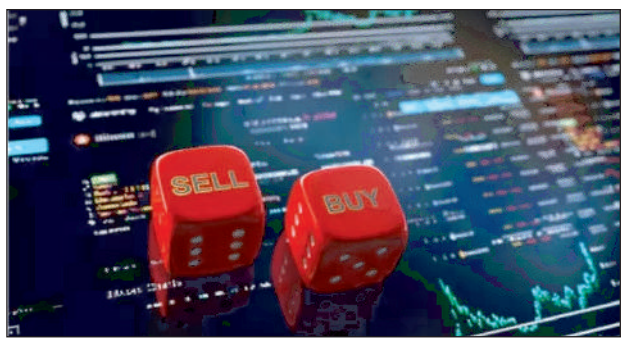

नई दिल्ली। आज सुबह शेयर बाजार सीमित दायरे में खुला था पर बाद में बाजार के दोनों सूचकांक हल्की बढ़त के साथ कारोबार करने लगे। बढ़त के कारोबार के बीच शुगर कंपनी राणा शुगर्स के शेयरों (Rana Sugars Shares) में बिकवाली आई।

शुरुआती कारोबार में ही कंपनी के स्टॉक 14 फीसदी तक गिर गए थे। हालांकि, बाद में कंपनी के शेयर उबर गए थे। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 7.02 फीसदी फिसलकर 21.72 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

शेयर में गिरावट की वजह

27 अगस्त 2024 (सोमवार) को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने राणा शुगर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। सेबी ने फंड्स की हेराफेरी का आरोप में कंपनी के प्रमोटरों और कुछ अधिकारियों को शेयर मार्केट से 2 साल के बैन कर दिया। इसके अलावा इनपर 63 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

सेबी ने कंपनी के इंदर प्रताप सिंह राणा (प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर), रणजीत सिंह राणा (चेयरमैन), वीर प्रताप राणा, गुरजीत सिंह राणा, करण प्रताप सिंह राणा, राजबंस कौर, प्रीत इंदर सिंह राणा और सुखजिंदर कौर पर भी रोक लगाई। अब यह सभी व्यक्ति दो साल तक किसी भी लिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनने या मैनेजमेंट में कोई अन्य अहम पद नहीं ले सकते हैं।

इसके अलावा सेबी ने राणा शुगर्स, उसके प्रमोटरों, अधिकारियों और अन्य रिलेटेड पार्टीज पर तीन करोड़ रुपये से लेकर सात करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया है।

सेबी के आदेश के अनुसार राणा शुगर्स के चीफ फाइनेंस ऑफिसर (CFO) मनोज गुप्ता पर PFUTP नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। मनोज गुप्ता कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर हस्ताक्षर करके उसे प्रमाणित करते हैं।

शेयर की परफॉर्मेंस

राणा शुगर्स ने पिछले एक साल में 13.29 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर बीते 6 महीने की बात करें तो कंपनी ने निवेशकों को 8.16 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Rana Sugars M-Cap) की वेबसाइट के अनुसार राणा शुगर्स का एम-कैप 333.86 करोड़ रुपये है।

जन-धन योजना के 10 साल पूरे, खुले 53 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते; महिलाओं की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

साल 2014 में PM Jan Dhan Yojana शुरू की गई थी। इस योजना को 10 साल हो गए हैं। विदेश में भी इस योजना की तारीफ की जाती है। देश में सभी नागरिकों के पास बैंक अकाउंट हो इसके लिए यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 53 करोड़ जनधन अकाउंट ओपन हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा महिलाओं के अकाउंट हैं।

नई दिल्ली। भारत सरकार ने सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट (Bank Account) हो इसके लिए साल 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना (PM Jan Dhan Yojana-PMJDY) शुरू की थी। इस योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। अगर योजना की सफलता की बात करें तो यह योजना लोगों को काफी पसंद आई।

जनधन के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाएं आगे

योजना में पुरुषों की तुलना में सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की थी। जन-धन अकाउंट (JanDhan Account) में महिलाओं की हिस्सेदारी 80 फीसदी है। योजना में महिलाओं की भागीदारी 2011 में 26 फीसदी और 2021 में 78 फीसदी हो गई थी। इन आंकड़ों से ही पता चलता है कि महिलाओं के बीच जनधन योजना काफी पॉपुलर है।

मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 53.13 करोड़ जनधन अकाउंट हैं। इन अकाउंट में से 30 करोड़ अकाउंट महिलाओं के हैं। 35 करोड़ अकाउंट ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खुले हैं। पीएम जन धन योजना ने बैंक अकाउंट के मामले में ग्रामीण-शहरी के अंतर को एकहद तक कम कर दिया।

योजना ने फाइनेंशियल सर्विस तक पहुंच में लैंगिक अंतर को भी एकहद तक कम कर दिया। वर्ष 2011 में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में लिंग अंतर 20 प्रतिशत था और 2017 में यह घटकर 6 प्रतिशत हो गया।

PM JanDhan योजना की विशेषता बनाती है इसे खास

अगस्त 2024 तक पीएम जनधन योजना के तहत 36.13 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड (Rupay Debit Card) जारी हो गए हैं। इन कार्ड को जारी करने में कोई राशि नहीं लगती है। इसके अलावा इस कार्ड पर खाताधारक को 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस बेनिफिट और 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि PMJDY अकाउंट में आई वृद्धि के बाद क्राइम रेट्स में गिरावट देखने को मिली है, जिससे समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

जनधन योजना की पॉपुलेरिटी देश के बाहर भी है। विदेश में भी इस योजना की तारीफ की जा रही है। 2023 में हुए G20 बैठक के बाद विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत ने अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को केवल 6 वर्षों में हासिल कर लिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है।

टैक्स रिफंड का कर रहे हैं इंतजार, जान लें विभाग को कितने दिनों में पूरा करना होता है रिटर्न प्रोसेस

परिवहन विशेष न्यूज

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद करदाता टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आईटीआर फाइल करने और रिफंड करने में कुछ समय लगता है। ऐसे में करदाता के मन में सवाल आता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितने दिन में रिटर्न का प्रोसेस पूरा होता है। अगर करदाता को रिफंड देर से मिलता है तो क्या उस पर ब्याज भी मिलता है?

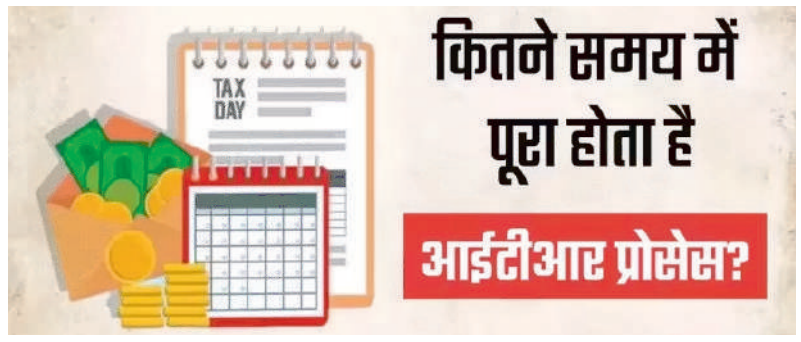

दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल किया नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जिन करदाता ने रिटर्न फाइल कर दिया है वह अब टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं।

कई करदाता के मन में सवाल है कि आयकर विभाग आईटीआर का प्रोसेस कब शुरू करेंगे और टैक्स रिफंड कितनी दिनों में आएगा। आपको बता दें कि जब करदाता ज्यादा टैक्स का भुगतान कर देते हैं तो आयकर विभाग अतिरिक्त टैक्स राशि को वापस कर देता है। आईटीआर को प्रोसेस करने के बाद विभाग बताता है कि करादाता को ज्यादा टैक्स देना है या फिर उसे रिफंड मिलेगा।

अगर आपने जुलाई में आईटीआर फाइल किया और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि आईटीआर प्रोसेस की प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

आईटीआर प्रोसेस होने में कितना समय लगता है?

आयकर विभाग को असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 9 महीने के भीतर आईटीआर प्रोसेस को पूरा करना होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी टैक्सपेयर ने जुलाई में रिटर्न फाइल किया है तो विभाग के पास आईटीआर को संसाधित करने के लिए दिसंबर तक का समय है। आईटीआर प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद अगर करदाता ने ज्यादा टैक्स दिया है तो विभाग को रिफंड करना होगा।

अगर किसी करदाता ने 31 जुलाई 2024 तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वह 31 दिसंबर 2024 तक पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल कर सकता है। हालांकि, लेट रिटर्न का प्रोसेस 31 दिसंबर 2024 के बाद शुरू होगा।

टैक्स रिफंड पर मिलता है ब्याज

अगर टैक्सपेयर टैक्स रिफंड के लिए योग्य हैं तो उन्हें उस पर ब्याज मिलता है। करदाता को तब ही ब्याज दिया जाता है जब रिफंड राशि वास्तविक टैक्स लाइबेलिटी का 10 फीसदी से ज्यादा हो।

उदाहरण के तौर पर अगर करदाता ने 20,000 रुपये का टैक्स दिया है और वास्तविक देनदारी 15,000 रुपये है तो उसे 5,000 रुपये रिफंड मिल जाएगा। इस रिफंड के साथ उसे ब्याज का लाभ भी मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 5,000 रुपये का आयकर रिफंड 15,000 रुपये की वास्तविक कर देनदारी का 10 फीसदी से ज्यादा है।

आयकर नियमों के अनुसार आयकर रिफंड पर प्रति माह 0.5 फीसदी का ब्याज देना अनिवार्य है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन साधारण ब्याज फार्मूले का इस्तेमाल करके किया जाएगा। अगर आईटीआर 31 जुलाई से पहले भरा जाता है तब ब्याज की गणना 1 अप्रैल से टैक्स रिफंड की तारीख तक होती है।

वहीं लेट आईटीआर फाइल करने पर टैक्स फाइल की तारीख से लेकर रिफंड जारी होने तक के दिन को कैलकुलेट करके ब्याज की गणना की जाती है।

क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम 2024: विकसित भारत 2047 को लेकर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज पर रहेगा फोकस

सभी की निगाहें क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम 2024 के दूसरे संस्करण पर टिक चुकी हैं। इस वर्ष का फोरम विकसित भारत 2047 के लिए क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के रोडमैप पर केंद्रित है जो भारत की रचनात्मक उद्योगों के व्यापार और बाजार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है।सिनेडारबार द्वारा आयोजित यह इवेंट एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों (सीसीआई) को समर्पित है।

नई दिल्ली। 31 अगस्त तारीख काफी नजदीक है इसी के साथ सभी की निगाहें क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम 2024 के दूसरे संस्करण पर टिक गई हैं। इस वर्ष का फोरम ₹विकसित भारत 2047₹ के लिए क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के रोडमैप पर केंद्रित है, जो भारत की रचनात्मक उद्योगों के व्यापार और बाजार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है।

सिनेडारबार द्वारा आयोजित यह इवेंट एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों (सीसीआई) को समर्पित है। यह आयोजन एक अग्रणी मंच के रूप में खड़ा है जो फिल्म, संगीत, फैशन, गेमिंग, प्रकाशन, हस्तशिल्प, कला, और संग्रहालय सहित विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों के नेताओं को एक साथ लाता है।

विभिन्न प्रतिभागियों के बीच सहयोग को देगा बढ़ावा फोरम

क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम की संस्थापक और सिनेडारबार की अध्यक्ष सुप्रिया सूरी ने कहा, "यह असाधारण फोरम उद्यमियों, कलाकारों, कानूनी विशेषज्ञों, नौकरशाहों, सरकारी अधिकारियों, राजदूतों और गिल्ड नेताओं सहित विभिन्न प्रतिभागियों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। इन विभिन्न क्षेत्रों की आवाज़ों को एकजुट करके, यह फोरम भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की परिभाषित आवाज़ बनने की आकांक्षा रखता है।

"विकसित भारत 2047₹ थीम के अनुरूप, इस आयोजन में कई सत्र होंगे जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए बौद्धिक संपदा का निर्माण, रचनात्मक अर्थव्यवस्था में नवाचार, पर्यटन पर रचनात्मक उद्योगों का प्रभाव, और वैश्विक बाजारों में निर्यात के लिए रणनीतियों जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।"

क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम के पहले एडिशन का उद्घाटन

संस्कृति मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 14 जुलाई 2023 को कल्चर 20: क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम (सीईएफ) के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया था। इस आयोजन का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद (राज्यसभा) डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेई और पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित सांसद (राज्यसभा) डॉ. सोनल मानसिंह ने किया था।

10 राज्यों में बनेंगी 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी, कैबिनेट ने लगाई मुहर

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में रेलवे सेक्टर के साथ कई और अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने इंडसट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम (National Industrial Corridor Development Programme) के तहत 12 इंडसट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी।

नई दिल्ली। आज दिल्ली में कैबिनेट और सीसीईए की बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।

कैबिनेट ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट इंडसट्रियल सिटी बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट और 234 नए शहरों के लिए प्राइवेट एफएम प्रोजेक्ट पर भी मुहर लग गई।

इंडसट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने नेशनल इंडसट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम (राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम) के तहत 12 इंडसट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने प्रोजेक्ट के लिए 28602 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। उम्मीद की जा रही है कि प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद इसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा।

भारत की ग्लोबल वैल्यू चेन की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार स्मॉर्ट इंडसट्रियल सिटी या इंडसट्रियल नोड्स की तैयार जमीन निवेशकों को ऑफर करेगी।

कहां बनेंगे स्मार्ट इंडसट्रियल सिटी

देश के 10 राज्यों में 12 स्मार्ट इंडसट्रियल सिटी बनाए जाएंगे। इसके अलावा मुख्य 6 कॉरिडोर को स्थापित किया जाएगा। इन शहरों में बनेंगे स्मार्ट इंडसट्रियल सिटी-

- उत्तराखंड में स्थित खुरपिया
- पंजाब में स्थित राजपुरा पटियाला
- महाराष्ट्र में दिघी
- केरल में पलक्कड़
- उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज
- बिहार में गया
- तेलंगाना में जहीराबाद
- आंध्र प्रदेश में ओरवक्कल और कोपारत्थी
- राजस्थान में जोधपुर पाली

यह सभी सिटी पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के दिशा के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इन सिटी में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित होगा। यह स्मार्ट सिटी प्लग एंड प्ले और वॉक टू वर्क कॉनसेप्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को इस तरह तैयार किया जाएगा जिससे निवेशकों को इन सिटीज में काम शुरू करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

जम्मू-कश्मीर चुनाव से नये दौर की उम्मीद

जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव अनेक दृष्टियों से न केवल राजनीतिक दशा-दिशा स्पष्ट करेंगे बल्कि बल्कि राज्य के उद्योग, पर्यटन, रोजगार, व्यापार, रक्षा, शांति आदि नीतियों तथा राज्य की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा।

जम्मू एवं कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की चुनाव आयोग की घोषणा निश्चित ही लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती देने के साथ क्षेत्र के लिए विकास के नए दौर के द्वार खोलने का माध्यम बनेगी। जम्मू-कश्मीर की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 43 जम्मू और 47 कश्मीर की सीटें हैं, इन चुनावों में जम्मू-कश्मीर के लोग सक्रिय रूप से भाग लेकर और बड़ी संख्या में मतदान कर ऐसी सरकार बनाये जो शांति और विकास के नये द्वार उद्घाटित करते हुए युवाओं के लिए उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करे एवं आतंकमुक्ति का एक नया अध्याय रचे। आज सबकी आंखें एवं कान चुनावी सरगर्मियों एवं भविष्य के गर्भ में ईवीएम से निकलने वाले जनादेश पर लगी हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ प्रांत में नई उम्मीदों के नये दौर का आगाज है। इस बार के चुनाव अब तक हुए चुनावों से अलग है और खास है।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामाकंन भरने की आज आखिरी तारीख है, लेकिन तमाम बड़ी पार्टियों के बीच असमंजस और अनिश्चितता जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि कुछ हद तक इस तरह की अनिश्चितता हर चुनाव में होती है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के मामले में हालात सामान्य से ज्यादा जटिल हैं और इस असमंजस के पीछे उसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्षी खेमे में माने जाने वाले राज्य के तीनों प्रमुख दलों में सहयोग और संघर्ष दोनों का दिलचस्प घालमेल दिख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सभी 90 सीटों पर गठबंधन की घोषणा कर दी गई है, लेकिन आलम यह है कि पहले चरण की 24 सीटों का भी बंटवारा मुश्किल साबित हो रहा। पीडीपी इस गठबंधन से बाहर है। फिर भी मुद्दों की एकरूपता के चलते न सिर्फ उमर अब्दुल्ला उससे अपनी पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी न खड़ा करने को कह रहे हैं बल्कि खुद महबूबा भी कह चुकी हैं कि अगर उनके अजेंडे को स्वीकार किया गया तो गठबंधन का समर्थन करेंगी। भाजपा किसी बड़े दल के साथ गठबंधन में नहीं है, इसलिए वहां इस तरह की गफलत नहीं है, लेकिन निर्णय लेना और उसे लागू करना वहां भी जटिल बना हुआ है। जम्मू-कश्मीर में दस वर्ष बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा को अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर उसे जिस तरह वापस लेना पड़ा, उससे उसकी छिछालेदार तो हुई ही है, अनुशासित दल की उसकी छवि को धक्का भी लगा। स्थिति यह है कि पार्टी ने सोमवार को 44 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के थोड़ी ही देर बाद व्यापक विरोध के कारण उसे वापस ले लिया। इसके बाद जो सूची जारी की गई, उसमें 15 ही प्रत्याशियों के नाम थे। यह आलम तब है, जब पहली सूची भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंजूर की गई थी।

यदि भाजपा औरों से अलग तथा अनुशासित दल की अपनी छवि के प्रति सचेत है तो उसे प्रत्याशी चयन की अपनी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक आकार देना ही होगा। पहले जारी सूची का विरोध जिन कारणों से हुआ, उनमें एक तो दूसरे दलों से आए नेताओं को प्रत्याशी बनाना रहा और दूसरे दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्रियों का नाम न होना। लगता है भाजपा को अभी भी लोकसभा चुनावों में हुई गलतियों का आभास नहीं है। लोकसभा चुनाव में उसे दूसरे दलों के नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का किस तरह नुकसान उठाना पड़ा था।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए जारी प्रत्याशियों की सूची का विरोध यह भी बताता है कि भाजपा प्रत्याशी चयन की कोई नीर-क्षीर, पारदर्शी और ऐसी प्रक्रिया का निर्माण नहीं कर सकी है, जिससे असंतोष, विरोध और भितरघात का सामना न करना पड़े। वैसे यह समस्या केवल भाजपा की ही नहीं, सभी दलों की है। कम से कम यह तो होना ही चाहिए कि राजनीतिक दल प्रत्याशियों के चयन में अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की राय को महत्व दें। यह कठिन कार्य नहीं, लेकिन हमारे राजनीतिक दल आंतरिक लोकतंत्र विकसित करने से बच रहे हैं।

चुनाव अभियान प्रारम्भ हो रहा है। प्रत्याशियों के नामांकन हो रहे हैं। सब राजनैतिक दल अपने-अपने 'घोषणा-पत्र' को ही गीता का सार व नीम की पत्ती बताकर सब समस्याएं मिटा देने तथा सब रोगों की दवा बन जाने की नैतिकता की बातें करते हुए व्यवहार में अनैतिकता को छिपायेंगे। टुकड़े-टुकड़े बिखरे कुछ दल फेवीकॉल लगाकर एक होंगे। सत्ता तक पहुँचने के लिए कुछ दल परिवर्तन को आकर्षण व आवश्यकता बतायेंगे। इस बार दलों में जितना अन्दर-बाहर होता हुआ दिख रहा है, उससे स्पष्ट है कि चुनाव परिणामों के बाद भी एक बड़ा दौर असमंजस का चलेगा। ऐसी स्थिति में मतदाता अगर बिना विवेक के आंख मूंदकर मत देगा तो परिणाम उस उक्ति को चरितार्थ करेगा कि "अगर अंधा अंधे को नेतृत्व देगा तो दोनों खाई में गिरेंगे।" इसलिये प्रांत के लोगों को मतदान करते हुए विवेक का परिचय देना होगा।

इन चुनावों की जटिलता का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि एक दशक पहले यानी 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के समय अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे से लैस जम्मू-कश्मीर अब विशेष राज्य के दर्जे से भी वंचित है। उस चुनाव में दो सबसे बड़ी और मिलकर सरकार बनाने वाली पार्टियां पीडीपी और भाजपा एक-दूसरे की धुर विरोधी हो चुकी हैं। राज्य में अब भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिन्दू बहुल सीटों और कश्मीरी पंडितों के वोट बैंक को अपने खाते में डालने के इरादे से मैदान में उतर रही है और ऐसे में कांग्रेस की हालत खराब होना तय माना जा रहा है। भले ही सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने भाजपा के साथ गठबंधन करने से इंकार कर दिया है, लेकिन भाजपा की मजबूत स्थिति को देखते हुए भविष्य में क्षेत्रीय दलों के भाजपा के साथ बहती हवा में जाने की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर एक राज्य के रूप में शुरू से विशिष्ट रहा है, इस दृष्टि से वहां होने वाले चुनाव भी विशेष एवं अन्य राज्यों से भिन्न है। बड़ी बात यह है कि पार्टियां एक-दूसरे के बारे में चाहे जो भी कहें, ये सभी भारतीय संविधान के तहत लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव में हिस्सेदारी कर रही हैं और जनादेश को भी स्वीकार करेंगी। निश्चित ही इन चुनाव परिणामों से उम्मीद जगी है कि यहां से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक विकास और शांति-समृद्धि-स्थिरता का नया दौर शुरू होगा। ऐसा होना ही इन चुनावों की सार्थकता है।

जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव अनेक दृष्टियों से न केवल राजनीतिक दशा-दिशा स्पष्ट करेंगे बल्कि बल्कि राज्य के उद्योग, पर्यटन, रोजगार, व्यापार, रक्षा, शांति आदि नीतियों तथा राज्य की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा। वैसे तो हर चुनाव में वर्ग, जाति, सम्प्रदाय का आधार रहता है, पर इस बार वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय व क्षेत्रीयता व्यापक रूप से उभर कर सामने आयेगी। मतदाता जहां ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहा है, वहीं राजनीतिज्ञ भी ज्यादा समझदार एवं चतुर बने हुए दिख रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार चुनावी शतरंज पर काले-सफेद मोहरें रखे हैं, उससे मतदाता भी उलझा हुआ है। अपने हित की पात्रता नहीं मिल रही है। कौन ले जाएगा राज्य की एक करोड लाख पच्चीस लाख जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विकास एवं शांति की दिशा में। सभी नंगे खड़े हैं, मतदाता किसको कपड़े पहनाएगा, यह एक दिन के राजा पर निर्भर करता है। चुनाव घोषित हो जाने से तथा प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से जो क्रियाएं-प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसने ही सबके दिमागों में सोच की एक तेजी ला दी है। प्रत्याशियों के चयन व मतदाताओं को रिझाने के कार्य में तेजी आती जायेगी। परम आवश्यक है कि सर्वप्रथम राज्य का वातावरण चुनावों के अनुकूल बने। राज्य ने साम्प्रदायिकता, आतंकवाद तथा अस्थिरता के जंगल में एक लम्बा सफर तय किया है। उसकी मानसिकता घायल है तथा जिस विश्वास के धरातल पर उसकी सोच ठहरी हुई थी, वह भी हिली है। पुराने चेहरों पर उसका विश्वास नहीं रहा। अब प्रत्याशियों का चयन कुछ उसूलों के आधार पर होना चाहिए न कि जाति और जीतने की निश्चितता के आधार पर। मतदाता की मानसिकता में जो बदलाव अनुभव किया जा रहा है उसमें सूझबूझ की परिपक्वता दिखाई दे रही है। ये चुनाव ऐसे मौके पर हो रहे हैं जब राज्य लम्बे दौर की विभिन्न चुनौतियों से जूझने के बाद शांति एवं विकास की राह पर अग्रसर है।

अब्दुल्ला परिवार के साथ जाने की कांग्रेस की क्या है मजबूरी? देशविरोधी बातों का समर्थन क्यों?

खास साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा इस सप्ताह जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव और भारतीय राजनीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी। इस दौरान प्रभासाक्षी संपादक ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में धारा 370 और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ-साथ साल 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का कार्यान्वयन करने का वादा किया है। पूर्ववर्ती राज्य विधानसभा से पारित यह प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर में 1953 से पहले की संवैधानिक स्थिति बहाल करने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि अब जब जम्मू-कश्मीर चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीटों का समझौता हो गया है तो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में किये गये वादों का समर्थन करती है?

प्रभासाक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे ने कहा कि अब्दुल्ला परिवार और कांग्रेस का बहुत पुराना नाता है। दोनों दलों के बीच परिवार और पार्टी का समझौता वर्षों से रहा है। वर्तमान में जो गठबंधन हुआ है वह सिर्फ सीटों के लिए हुआ है। हालांकि कांग्रेस को कुछ सवालों का अब जवाब देना होगा जो बीजेपी उठा रही है, देश भी उठा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या जम्मू कश्मीर को लेकर नेशनल कांफ्रेंस ने अपने मेनिफेस्टो में जो बातें की थी, उसका समर्थन करती है? उमर अब्दुल्ला 370 और 35ए को फिर से लागू करने की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? उमर अब्दुल्ला ने एक वक्त पर जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की बात की थी, क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? फिर से दो झंडे की बात हो रही है, क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? क्या पाकिस्तान से व्यापार का कांग्रेस समर्थन कर रही है? क्या हरी पर्वत और शंकराचार्य पर्वत का नाम बदले जाने का कांग्रेस समर्थन कर रही है? अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं उसे पर कई सवाल खड़े होंगे।

मंथन साहित्यिक परिवार की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी सम्पन्न

परिवहन विशेष न्यूज

मंथन साहित्यिक परिवार की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी रेखा राठौर सुसनेर (म. प्र.) की अध्यक्षता , सुभाषचन्द्र शर्मा जयपुर के मुख्य आतिथ्य, कविता व्यास रतलाम के विशिष्ट आतिथ्य, बच्चूलाल दीक्षित, म.प्र. के संयोजकत्व तथा डॉ मनीष दवे, इंदौर के संचालन में संपन्न हुई।

प्रथमतः सुभाषचंद्र शर्मा से देश के ज्वलंत मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा से शुरुआत हुई। उन्होंने नीरज, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर जैसी महान प्रतिभाओं से प्रभावित होकर प्रेरणा लेने की बात कही। फिर आगंतुक कवियों ने रचना पाठ किया। बृज व्यास (पूना) का गीत नरपिशाची सोच ने जीना किया दुस्सार है, गीता उनियाल (उत्तराखंड) सुविचार पर, राजेश शर्मा (नागपुर) वर्षा की बूंद गिरती है मेरे आंगन में और मेरे दिल में विरह की आग लग जाती है, कविता पूणताम्बेकर (शाजापुर) समय के साथ चलना तुम सफर मुश्किल नहीं होगा, भले कांटों भरा रास्ता, डॉ. शिवदत्त शर्मा (जयपुर) कहां छुपे हो मुरली वाले किसको गीता सुना रहे हो, बेला विरदी (हरियाणा) खड़ा वृक्ष क्षण में सहम गया हिलकर अपनी जड़ तक,

विशिष्ट अतिथि कविता व्यास विवेक (रतलाम) गोविंद ज्ञानेश्वर हरि माधव मोहन और मुरलीधर क्या लिखें इस बनावटी युग से, गिरीश पाण्डेय (काशी) चुरा के नींद जो बैठा है मेरी रातों की, उसे भी इश्क हो जीना हराम हो जाए। मैं संग (पत्थर) होके भी पारस के साथ रहता हूँ।कभी तो मेरा सोने सा दाम हो जाए।

वहीं प्रतिभा पाण्डेय (चैन्नई) ने आज शोर बेहिसाब हो रहा है, हर दिल में अलाव जल रहा है, बेलाजी की प्रतिक्रिया आज हाथों में उछलती पट्टियां फिर भी गांधारी के आंखों पे बंधीं हैं पट्टियां, संगीता माहेश्वरी (मनासा, नीमच) जीवन में सुख-दुख के मौसम हैं आते जाते, मुख्य अतिथि सुभाष शर्मा (जयपुर) अंतर्मन की पीडा.- नैनों से बह रहे आज आंसुओं को बह जाने दो घनी भूत है अंतर्मन की पीड़ा को बह जाने दो, प्रकाश हेमावत (रतलाम) की निर्भया की नृशंस हत्या पर पीडा.आंसू इस बात की गवाह दे रहे हैं फांसी क्यों नहीं हुई, प्रो.राम पंचभाई (यवतमाल, महाराष्ट्र) एक क्षत विक्षत बेटी का बलात्कार हुआ है। इसी वाक्य पर बेलाजी, शिवदत्तजी के साथ सुभाष जी आदि की आंखे रचना के अंतिम शब्द रचैनल बदला गीत आ रहा था तूं चीज बडी.है मस्त मस्तरइसी क्रम में संजय एम तराणेकर, फ़िल्मि समीक्षक (इंदौर) हे कृष्ण आओगे ना हे मुरलीधर आओगे ना इन दुःशासनों पर चक्र बरसाओगे ना, इंजी. खण्डेलवाल (ब्रजवासी) निर्भया खूब टटोल रही है आज उस आत्मा को लेकर फिर बोल रही है, कैलाश वशिष्ठ (रतलाम) उड़ते गगन चाहे पंछी को पंख दे, बच्चूलाल दीक्षित (ग्वालियर) की जंगलराज पर प्रस्तुति उपरांत रेखा राठौर ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कवियों की प्रस्तुतियों की क्रमवार समीक्षा करते हुए काव्यगोष्ठी को नारी सशक्तीकरण निरूपित किया।

डॉ मनीष दवे ने आभार व्यक्त करते हुए बंगाल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की नृशंस हत्या पर कठोरतम दंड अविलम्ब देने का सरकार को पटल की ओर से भेजने का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वानुमति से पारित किया गया।

तेरी अदाओं का कायल हूँ.

मैं तेरी अदाओं का कायल हूँ.
ज़बसे देखा हैं तुझे घायल हूँ.
सोचता हूँ कभी-कभी,
मैं ही तेरे पैरों की पायल हूँ.
चेहरा ऐसे न छुपाया कर,
जानेमन अपने हाथों से
किसी दिन मुझे भी देख लेना,
अपनी नूरानी सी नज़रों से
कहती हैं ये दुनियाँ मैं रॉयल हूँ.
सुना तुझे खूबसूरती पर नाज़ हैं,
पर बड़ी खराब तेरी आवाज़ हैं.
विनम्रता की चादर ओढ़ना,
इसी भाव से सबको जोड़ना.
मैं भले कन्हैया न बन सका,
तू राधा बन मटकी ले दौड़ना.
हाँ, तुझ पर मैं फ़िदा हूँ,
क्योंकि अभी-भी,
मैं तेरी अदाओं का कायल हूँ.

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
98260 25986

प्रथम पूज्य गणपति प्रतिमाओं का वितरण होगा 7 सितंबर को

समिति द्वारा तैयार करवाई गई 300 छोटी व बड़ी गणेश प्रतिमाएं वितरण को तैयार

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वाधान 10 दिवसीय गणेश महोत्सव के आयोजन के तहत प्रथम पूज्य गणपति प्रतिमाओं का वितरण 7 सितंबर शनिवार को गणेश चतुर्थी के दिन आर सी व्यास कॉलोनी स्थित अपना घर वृद्धाश्रम मे प्रातः 9 बजे किया जाएगा

समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इंदौर से आए प्रमुख मूर्तिकार बृजमोहन के नेतृत्व में पाच मूर्तिकारो द्वारा समिति द्वारा छोटी व बड़ी 300 गणपति प्रतिमाएं तैयार करवाई गई है जो वितरण के लिए तैयार है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है जिसमें जुट, मिट्टी व नेचुरल कलर का उपयोग कर बनाई गई,इको फ्रेंडली होने से गणपति प्रतिमाओं को जलाशय में विसर्जन करने पर प्रदूषण नहीं होगा ,समिति के अध्यक्ष उदयलाल समदानी एवं कोषाध्यक्ष सुभाष अग्रवाल के अनुसार इस बार भी भीलवाड़ा जिले सहित पांच जिलों में गणपति की मूर्तियां वितरित की जाएगी समिति द्वारा 5 फीट व डेट फिट की गणपति प्रतिमाओं को मूर्तिकारों द्वारा अंतिम रूप देकर तैयार किया गया है पंजियन की गई संस्था को 7 सितंबर के दिन गणेश चतुर्थी को वितरित की जाएगी गणपति प्रतिमाओं का विभिन्न गणपति आयोजन समितिया, मोहल्ला, संस्थाओं द्वारा गणेश महोत्सव आयोजन हेतु प्रतिमाओं का पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है पंजीयन की गई प्रतिमाओं के टोकन दिए जाएंगे जिसे गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद वितरित किया जाएगा

आचार्य बिहार ट्रैफिक में हाइवा ने बोलेरो को टक्कर मार दी

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वर : आचार्य बिहार ट्रैफिक में हाइवा ने बोलेरो को टक्कर मार दी और आचार्य बिहार स्थित ट्रैफिक पोस्ट पर चढ़ गयी ।रात में हाईवा ने बोलेरो में टक्कर मार दी। हाइवा अपोलो अस्पताल से होकर आचार्य बिहार की ओर आ रही थी, तो बोलेरो वाणीविहार से होकर आचार्य बिहार की ओर आ रही थी ।लेकिन, आचार्य बिहार के ट्रैफिक में बोलेरो ने टक्कर मार दी और आचार्य बिहार के ट्रैफिक पोस्ट पर चढ़ गये । जिससे पूरा ट्रैफिक पोस्ट ध्वस्त हो गया और बोलेरो का एक तरफ का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया । हादसे में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ । गौरतलब है कि बोलेरो में एक ही सवार था, जबकि हाइवा में दो सवार थे। हादसे के बाद बोलेरो सवार को मामूली चोटें आईं। उन्हें कैपिटल हॉस्पिटल ले जाया गया । हाइव घटनास्थल से भाग गया है। शहीद नगर पुलिस ने हाइवा और बोलेरो दोनों को जब्त कर लिया है और घटना की आगे की जांच कर रही है ।

सरकार ने 191 अवैध अपार्टमेंट को तोड़ने का आदेश दिया

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वर : सबसे ज्यादा अवैध अपार्टमेंट राजधानी भुवनेश्वर में बन रहे हैं । भुवनेश्वर राज्य का प्रमुख शहर है।इस महानगरीय क्षेत्र में समय-समय पर कई अवैध अपार्टमेंट बनते रहे हैं। राज्य सरकार ने राजधानी में बने 191 अवैध अपार्टमेंट को तोड़ने का आदेश दिया है । भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने कुल 491 अवैध अपार्टमेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 237 मामले लंबित हैं जबकि 63 खारिज हो चुके हैं । सरकार ने बाकी 191 अवैध अपार्टमेंट को तोड़ने का आदेश दिया ।

सिर्फ बीडीए ही नहीं, बल्कि भुवनेश्वर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन (बीएमसी) के अंतर्गत भी कई अवैध अपार्टमेंट बने हैं। अपार्टमेंट/इमारतों के अवैध निर्माण के खिलाफ 1444 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 451 मामलों का फैसला हो चुका है। 993 मामले लंबित हैं । उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ओडिशा विकास प्राधिकरण अधिनियम-1982 के तहत कार्रवाई की जा रही है। आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने मंगलवार को विधानसभा में कांग्रेस सदस्य ताराप्रसाद भागरपति के लिखित प्रश्न के उत्तर में यह बात कही ।

यदि सरकार के निर्णय के अनुसार अपार्टमेंट अवैध है यदि यह टूट जाता है, तो इसे खरीदने वाले ग्राहक को नुकसान होने का खतरा होता है। राजधानी में पिछले कुछ सालों से बने अवैध अपार्टमेंटों को तोड़ने का आदेश सरकार ने दिया है, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। न तो बीडीए और न ही बीएमसी एक भी अवैध इमारत को ध्वस्त कर पाई है क्योंकि उन अपार्टमेंट के मालिक अदालत के दरवाजे पर हैं। नगर विकास मंत्री की अधिसूचना के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023